

Progressive Research Journal

(A Peer Reviewed Journal of Education and social Sciences)
(Bilingual Half-Yearly Journal)



Prof. Shri Prakash Mishra
Chief-Editor

Dr Ramanand Tiwari
Managing Editor

VOL 26

NO 2

June 2025

AWADH EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH INSTITUTE, GONDA-UP 271209

Collaborate with M.L.K. P.G. College, Balrampur, U.P.

प्रकाशक— अवध शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, गोण्डा, उ०प्र०
बी०एड् विभाग, महारानी लाल कुँवरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलरामपुर

Reg 399/2011-12

EDITORIAL BOARD

PATRONS

- **Dr. O.P. Mishra** – Ex Principal, MLK PG College, Balrampur
- **Dr. J.P. Pandey** – Principal, MLK PG College, Balrampur
- **Dr. R.K. Pandey** – Principal, LBS PG College, Gonda

CHIEF EDITOR

- **Prof. Dr. Shri Prakash Mishra** – Professor, Department of B.Ed., M.L.K. P.G. College, Balrampur

MANAGING EDITOR

- **Dr. Ramanand Tiwari** – Secretary, Awadh Institute of Education and Social Sciences Research

ADVISORY COMMITTEE

Prof Vijay Kumar, Dean, Faculty of Education, Siddharth University Kapilvastu, Siddharthnagar

Prof Brijesh Kumar Pandey, Principal Ram Ji Sahay PG College Rudrapur, Deoria

Prof Sanjay Nimbalkar, Dept. of Education, Seva Sadan College of Education, Ihasnagar, Mumbai

Prof R P Pathak, Ex Head & Dean, Shiksha Vidyapeeth, L B S National Sanskrit

University(Central), New Delhi

Prof. Raghvendra Singh – Head, Department of B.Ed., M.L.K. P.G. College, Balrampur

Dr. Ragni Kumari – Head, Department of Optometry, U.P. Institute of Medical Science, Etawah

Dr. Ram Rahis – Assistant Professor, Department of B.Ed., M.L.K. P.G. College, Balrampur

Dr. Manik Mohan Shukla – Head, Department of B.Ed., A.M. College, Bodhgaya, Bihar

Dr. Ranjan Sharma – Head, Department of Geography, L.B.S. P.G. College, Gonda

Dr. A.K. Singh – Ex. Dean, Faculty of Education, Siddharth University, Siddharthnagar, U.P.

Dr. Bhawna Mishra – Principal, Siddhi Vinayak P.G. College, Gonda

Dr. Rekha Vishwakarma – Head, Department of Geography, M.L.K. P.G. College, Balrampur

Dr. Upendra Kumar – Head, Department of B.Ed., R.S.P. College, Jhariya, Dhanbad, Jharkhand

Dr. Sandeep Srivastava – Head, Department of B.Ed., L.B.S. P.G. College, Gonda

Mr. Narendra Kumar Mishra - Ex Faculty of B.Ed., Bodhgaya, Bihar.

Dr. Mukesh Kumar - Lecturer, College of Teacher Education(CTE) Gaya, Bihar

REGISTRATION & CONTACT

Prof. Shri Prakash Mishra

- Department of B.Ed. M.L.K. P.G. College, Balrampur, U.P.
- 9450516581

Office: Awadh Shiksha evam Samajik Vigyan Anusandhan Sansthan, Gonda, U.P. 271209

Mobile: 9455466863

Email- progressiveresearchjournal@gmail.com

Website- www.prjournal.in

संपादकीय

समकालीन युग में जब वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों ने मानव जीवन को सुविधा तो दी है, किंतु साथ ही नैतिक मूल्यों, सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय रिश्तों को गहन संकट में डाल दिया है, ऐसे समय में शोध और चिंतन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। **Progressive Research Journal** इसी आवश्यकता की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है, जो ज्ञान, विचार और विवेक के समन्वय से समाज को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करता है।

यह पत्रिका केवल शोध निष्कर्षों का संकलन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा वैचारिक मंच है जहाँ शिक्षा, समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और नैतिकता से जुड़े समकालीन प्रश्नों पर तर्कसंगत, तथ्यपरक और नवोन्मेषी विमर्श प्रस्तुत किया जाता है। आज आवश्यकता है कि शोध केवल अकादमिक उपाधि तक सीमित न रहकर समाज के वास्तविक सरोकारों से जुड़े और **Progressive Research Journal** इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है।

प्रस्तुत अंक में सम्मिलित शोध लेख विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं। यह पत्रिका नवोदित शोधार्थियों, प्राध्यापकों और विद्वानों को एक साझा मंच प्रदान करती है, जहाँ मौलिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय दिखाई देता है। हम यह मानते हैं कि सार्थक शोध वही है जो समाज को सोचने, बदलने और बेहतर बनाने की प्रेरणा दे।

अंत में, हम सभी लेखकों, समीक्षकों और पाठकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके बौद्धिक सहयोग से यह अंक संभव हो सका। हमें विश्वास है कि यह प्रयास शोध की गुणवत्ता, वैचारिक प्रगतिशीलता और सामाजिक चेतना को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

प्रो० श्री प्रकाश मिश्र

प्रधान संपादक

Progressive Research Journal

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
1.	बौद्ध शिक्षा दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत एवं उसका शैक्षिक महत्व	1-5
	आशीष कुमार पाठक	
2.	समकालीन शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का क्षरण : कारण, प्रभाव एवं समाधान	
	डॉ० रामानन्द तिवारी	6-12
3.	वैश्विक—मानक संस्थाओं का विकास : एन०ई०पी० 2020 के सन्दर्भ में	13-18
	डॉ० मनिक मोहन शुक्ल	
4.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वैदिक शिक्षा के संदर्भ में विश्लेषण	19-25
	डॉ० श्री प्रकाश मिश्र	
5.	Creation of Globally Competent Teachers in the Light of National Education Policy (NEP) 2020: An Indian Perspective	
	Dr. Mukesh Kumar, Dr. Neeta Singh	26-37
6.	Integration of Technology in Education under (National Education Policy) NEP 2020	
	Dr. M.M. Shukla, Rani Neena Priyadarshini	38-44
7.	State, Law, and Lawlessness: Failure of the Governance in Train to Pakistan	45-52
	Aditi Rai, Dr. Tulika Tripathi	
8.	शिक्षण शैलियों का माध्यमिक छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव: पटना जिले का एक शोध	
	मधु कुमारी, डॉ० गीता पाण्डेय	53-61

बौद्ध शिक्षा दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत एवं उसका शैक्षिक महत्व

आशीष कुमार पाठक
शोध-छात्र, शिक्षा संकाय,
सनराइज विश्वविद्यालय, राजस्थान

सार

प्रस्तुत शोध पत्र में बौद्ध दर्शन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं केन्द्रीय सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद (द्वादश निदान) का दार्शनिक तथा शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु एवं घटना कारणद्वारा संबंध पर आधारित होती है और कोई भी तत्व स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होता। यह सिद्धांत जीवन के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह प्रतिपादित करता है कि मानव जीवन में विद्यमान दुःखों का मूल कारण अज्ञान (अविद्या) एवं तृष्णा है।

इस शोध पत्र में प्रतीत्य समुत्पाद की बारह कड़ियों अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति तथा जरामरणकृका क्रमबद्ध एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार ये कड़ियाँ परस्पर संबद्ध होकर जन्मदुमरण के चक्र (भवचक्र) को संचालित करती हैं तथा मानव को दुःख के बंधन में रखती हैं। इसके अतिरिक्त, शोध पत्र में इस सिद्धांत के दार्शनिक महत्व का विवेचन करते हुए यह दर्शाया गया है कि यह शाश्वतवाद एवं उच्छेदवाद दोनों का खंडन कर मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है तथा आगे चलकर शून्यवाद के विकास का आधार बनता है।

शैक्षिक दृष्टिकोण से प्रतीत्य समुत्पाद का विशेष महत्व है। यह सिद्धांत शिक्षा को तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं कारणदृष्टिपरिणाम की समझ प्रदान करता है। साथ ही यह विद्यार्थियों में आत्मविश्लेषण, नैतिकता, उत्तरदायित्व तथा कर्मप्रधान जीवन-दृष्टि का विकास करता है। इस प्रकार यह शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रखकर उसे जीवनोपयोगी, मूल्यपरक एवं व्यावहारिक बनाता है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रतीत्य समुत्पाद न केवल बौद्ध दर्शन का मूल आधार है, बल्कि आधुनिक शिक्षा में भी इसकी प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानव जीवन को यथार्थ, नैतिक एवं संतुलित दृष्टि प्रदान करता है।

मुख्य शब्द— बौद्ध दर्शन, प्रतीत्य समुत्पाद, द्वादश निदान, शिक्षा, नैतिकता, कर्म

प्रस्तावना

शिक्षा और दर्शन का परस्पर गहरा एवं यथार्थवादी भी है। महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन के अविच्छिन्न संबंध है। किसी भी समाज की दुःखों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनके कारणों एवं शिक्षा-व्यवस्था उसके दार्शनिक आधारों, सांस्कृतिक निवारण का वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत मार्ग प्रस्तुत मूल्यों तथा जीवन-दृष्टि पर निर्मित होती है। दर्शन किया। उन्होंने जीवन को किसी दैवी या अलौकिक जहाँ जीवन के अंतिम सत्य, उद्देश्य एवं मूल्यों का शक्ति पर निर्भर न मानकर, उसे कारणद्वारा संबंधों अन्वेषण करता है, वहीं शिक्षा उन आदर्शों को व्यवहार की श्रृंखला के रूप में समझाया।

में रूपांतरित करने का माध्यम है। इस प्रकार शिक्षा, इसी संदर्भ में प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दर्शन की व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य बौद्ध दर्शन का केन्द्रीय तत्व है। यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु एवं

भारतीय चिंतन परंपरा में बौद्ध दर्शन एक घटना विभिन्न कारणों एवं परिस्थितियों पर निर्भर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह दर्शन न केवल होकर उत्पन्न होती है। कोई भी तत्व स्वतंत्र या आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि स्वायत्त रूप से अस्तित्व में नहीं होता। इस प्रकार यह

सिद्धांत जीवन के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह दर्शाता है कि मानव जीवन में विद्यमान दुःख अज्ञान (अविद्या) और तृष्णा के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दुःख के कारणों को समझकर उनका निराकरण किया जाए, तो दुःख से मुक्ति संभव है। यह सिद्धांत न केवल दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि शैक्षिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह व्यक्ति को तार्किक, विवेकपूर्ण एवं उत्तरदायी जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है।

अतः प्रस्तुत शोध पत्र में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का दार्शनिक एवं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है, जिससे इसके व्यावहारिक महत्व एवं आधुनिक शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता को समझा जा सके।

प्रतीत्य समुत्पाद का दार्शनिक स्वरूप

बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद (क्मचमदकमदज क्तपहपदंजपवद) का सिद्धांत अत्यंत केंद्रीय एवं मूलभूत स्थान रखता है। 'प्रतीत्य' का अर्थ है कृ प्रत्ययों (कारणों) पर निर्भर होना तथा 'समुत्पाद' का अर्थ है उत्पत्ति या प्रादुर्भाव। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का अभिप्राय है "कारणों एवं परिस्थितियों के आधार पर उत्पत्ति"।

इस सिद्धांत के अनुसार संसार की कोई भी वस्तु, घटना अथवा अवस्था स्वतः, स्वतंत्र या निरपेक्ष रूप से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वह विभिन्न कारणों एवं सहायक परिस्थितियों के संयोग से अस्तित्व में आती है। यह दृष्टिकोण समस्त अस्तित्व को एक परस्पर-निर्भर एवं गतिशील प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रत्येक तत्व अन्य तत्वों से जुड़ा हुआ है।

प्रतीत्य समुत्पाद का यह सिद्धांत बौद्ध दर्शन की यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। यह न केवल संसार के स्वरूप को समझने का प्रयास करता है, बल्कि मानव जीवन में दुःख के कारणों का भी तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

इसके अनुसार अज्ञान (अविद्या) के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा के कारण दुःख की उत्पत्ति होती है।

दार्शनिक दृष्टि से यह सिद्धांत दो अतिवादी मान्यताओं का खंडन करता है—

शाश्वतवाद— यह मान्यता कि संसार या आत्मा का अस्तित्व स्थायी एवं अपरिवर्तनीय है। प्रतीत्य समुत्पाद इस विचार को अस्वीकार करता है, क्योंकि इसके अनुसार सभी वस्तुएँ कारणों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं और परिवर्तनशील हैं।

उच्छेदवाद — यह धारणा कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ पूर्णतः समाप्त हो जाता है और किसी प्रकार की निरंतरता नहीं रहती। बौद्ध दर्शन इस मत का भी खंडन करता है, क्योंकि कारण, कार्य संबंध के आधार पर अस्तित्व की एक निरंतर प्रक्रिया बनी रहती है।

इन दोनों अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच मध्यम मार्ग का प्रतिपादन प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से किया गया है। यह दृष्टिकोण संतुलित, यथार्थवादी और तर्कसंगत है, जो जीवन के सत्य को न तो पूर्णतः स्थायी मानता है और न ही पूर्णतः नश्वर।

आगे चलकर बौद्ध आचार्य नागार्जुन ने इसी सिद्धांत को आधार बनाकर शून्यवाद का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार जब सभी वस्तुएँ परस्पर निर्भर हैं और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो वे स्वभावतः "शून्य" हैं। यहाँ 'शून्यता' का अर्थ शून्य या रिक्तता नहीं, बल्कि स्वतंत्र सत्ता के अभाव से है।

द्वादश निदान (प्रतीत्य समुत्पाद की बारह कड़ियाँ)

बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए इसे बारह परस्पर संबंधित कड़ियों या अवस्थाओं में प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। ये कड़ियाँ मानव जीवन के जन्मदमरण चक्र (भवचक्र) को स्पष्ट करती हैं तथा यह दर्शाती हैं कि किस प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य दुःख के बंधन में फँसा रहता है।

ये बारह कड़ियाँ निम्नलिखित हैं—

अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति एवं जरामरण।

इन सभी कड़ियों का संबंध कारणद्वारा के रूप में एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहाँ प्रत्येक कड़ी अगली कड़ी को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यह एक सतत प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसे भवचक्र कहा जाता है।

द्वादश निदानों का क्रमिक विश्लेषण

प्रथम कड़ी अविद्या है, जो वास्तविकता के अज्ञान को दर्शाती है। इसी अज्ञान के कारण व्यक्ति गलत धारणाओं एवं आसक्तियों में बँध जाता है। अविद्या के परिणामस्वरूप संस्कार उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति के कर्मों एवं मानसिक प्रवृत्तियों का निर्माण करते हैं। संस्कारों के प्रभाव से विज्ञान (चेतना) उत्पन्न होता है, जो जीवन के अनुभवों को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके पश्चात नामरूप का विकास होता है, जिसमें मानसिक एवं शारीरिक तत्वों का समन्वय होता है। नामरूप के आधार पर षडायतन अर्थात् छह इन्द्रियों का विकास होता है, जो बाह्य जगत के साथ संपर्क स्थापित करती हैं। इन्द्रियों और विषयों के संपर्क से स्पर्श उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप वेदना (सुख, दुःख या उदासीनता) की अनुभूति होती है।

वेदना के आधार पर तृष्णा उत्पन्न होती है, जो इच्छा एवं लालसा का रूप है। यही तृष्णा आगे उपादान (आसक्ति) में परिवर्तित होती है, जहाँ व्यक्ति किसी वस्तु, विचार या संबंध के प्रति गहरे मोह में बँध जाता है।

उपादान से भव उत्पन्न होता है, जो कर्मजनित अस्तित्व या जीवन की निरंतरता को दर्शाता है। भव के परिणामस्वरूप जाति (जन्म) होती है, और जन्म के साथ ही जरामरण (बुढ़ापा एवं मृत्यु) तथा उससे संबंधित शोक, दुःख एवं कष्ट उत्पन्न होते हैं।

भवचक्र का तात्पर्य

इन बारह कड़ियों का परस्पर संबंध यह स्पष्ट करता है कि मानव जीवन एक निरंतर चक्र है, जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का क्रम चलता रहता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक अविद्या और तृष्णा का निवारण नहीं होता।

संक्षिप्त रूप में श्रृंखला

इस जटिल प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है—

अविद्या → तृष्णा → उपादान → भव → जाति → दुःख (जरामरण)

यह श्रृंखला यह स्पष्ट करती है कि दुःख का मूल कारण अज्ञान और इच्छा है। यदि इन कारणों को समाप्त कर दिया जाए, तो दुःख का निवारण संभव है।

प्रतीत्य समुत्पाद का दार्शनिक महत्व

बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह संपूर्ण बौद्ध दर्शन की आधारशिला के रूप में स्थापित होता है। यह सिद्धांत अस्तित्व, ज्ञान एवं जीवन के स्वरूप को समझने के लिए एक वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके दार्शनिक महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है—

1. कारण-कार्य संबंध का वैज्ञानिक प्रतिपादन

प्रतीत्य समुत्पाद यह प्रतिपादित करता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु एवं घटना किसी न किसी कारण पर आधारित होती है। कोई भी वस्तु स्वतः उत्पन्न नहीं होती। यह सिद्धांत प्राकृतिक नियमों की भाँति कार्य करता है, जहाँ प्रत्येक परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य निहित होता है। इस प्रकार यह दर्शन जीवन को अंधविश्वास से हटकर तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।

2. स्वतंत्र सत्ता (ईश्वर-आत्मा) के अस्तित्व को चुनौती

यह सिद्धांत किसी भी स्वतंत्र, शाश्वत एवं स्वायत्त सत्ता जैसे ईश्वर या आत्माकृको स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार सभी वस्तुएँ परस्पर निर्भर हैं और उनका अस्तित्व अन्य कारणों पर आधारित है। इस प्रकार यह ईश्वरवाद एवं आत्मवाद दोनों की

परंपरागत धारणाओं को चुनौती देता है और एक नवीन दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

3. शून्यवाद का आधार

बौद्ध आचार्य नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को आधार बनाकर शून्यवाद का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार जब सभी वस्तुएँ परस्पर निर्भर हैं और उनका कोई स्वतंत्र स्वभाव (स्वभाव-शून्यता) नहीं है, तो वे 'शून्य' हैं। यहाँ शून्यता का अर्थ नकारात्मक रिक्तता नहीं, बल्कि स्वतंत्र सत्ता के अभाव से है। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद शून्यवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार करता है।

4. यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक जीवन-दृष्टि का विकास

यह सिद्धांत जीवन को किसी रहस्यवादी या अलौकिक दृष्टि से नहीं, बल्कि यथार्थवादी एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। यह मनुष्य को यह समझने में सहायता करता है कि उसके जीवन में घटित प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण होता है, जिसे समझकर वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है।

5. मध्यम मार्ग का दार्शनिक आधार

प्रतीत्य समुत्पाद शाश्वतवाद (सब कुछ स्थायी है) और उच्छेदवाद (सब कुछ नष्ट हो जाता है) दोनों का खंडन करता है। इस प्रकार यह संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। यह दृष्टिकोण जीवन में संतुलन, संयम और विवेक की भावना को विकसित करता है।

6. नैतिकता और उत्तरदायित्व का आधार

चूँकि यह सिद्धांत कर्म और उसके परिणामों को महत्व देता है, इसलिए यह व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग और उत्तरदायी बनाता है। यह विचार नैतिक जीवन के

निर्माण में अत्यंत सहायक है, क्योंकि व्यक्ति यह समझता है कि उसके वर्तमान कार्य ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रतीत्य समुत्पाद केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक जीवन-दृष्टि प्रदान करता है, जो मानव को तर्क, नैतिकता, संतुलन और यथार्थ के मार्ग पर अग्रसर करती है।

शैक्षिक महत्व

बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत केवल दार्शनिक अवधारणा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत व्यापक एवं व्यावहारिक महत्व है। यह सिद्धांत शिक्षा को यथार्थवादी, तार्किक एवं जीवनोपयोगी दिशा प्रदान करता है। इसके प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हैं—

1. तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

प्रतीत्य समुत्पाद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण पर आधारित होती है। इस प्रकार यह विद्यार्थियों में कारणदृष्टिपरिणाम संबंध को समझने की क्षमता विकसित करता है। इससे उनमें अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किकता का विकास होता है।

2. आत्मविश्लेषण एवं चिंतन क्षमता का विकास

यह सिद्धांत विद्यार्थियों को अपने विचारों, भावनाओं एवं कार्यों का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। वे यह समझने लगते हैं कि उनके व्यवहार के पीछे कौन-से कारण कार्य कर रहे हैं तथा उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। इससे उनमें गहन चिंतन एवं आत्ममूल्यांकन की प्रवृत्ति विकसित होती है।

3. नैतिकता एवं चरित्र निर्माण

प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध कर्मफल के सिद्धांत से है, जिसके अनुसार प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। यह विचार विद्यार्थियों को नैतिक जीवन जीने के लिए

प्रेरित करता है। वे अपने आचरण में सत्य, अहिंसा, करुणा एवं सदाचार को अपनाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके चरित्र का समुचित विकास होता है।

4. समस्या-समाधान क्षमता का विकास

यह सिद्धांत विद्यार्थियों को यह सिखाता है कि किसी भी समस्या के पीछे कुछ कारण होते हैं। यदि उन कारणों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाए, तो समस्या का समाधान संभव है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच एवं समस्या-समाधान की क्षमता को विकसित करता है।

5. कर्मप्रधान एवं उत्तरदायी दृष्टिकोण का विकास

प्रतीत्य समुत्पाद यह प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। इससे विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना विकसित होती है। वे यह समझते हैं कि उनके वर्तमान कार्य ही उनके भविष्य का निर्माण करते हैं।

6. समग्र व्यक्तित्व विकास

यह सिद्धांत व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं भावनात्मक सभी पक्षों के संतुलित विकास पर बल देता है। इससे शिक्षा केवल सूचना-प्रदाय तक सीमित न रहकर व्यक्तित्व के समग्र विकास का माध्यम बन जाती है।

निष्कर्ष

प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूलभूत सिद्धांत है, जो मानव जीवन के दुःखों की व्याख्या एवं उनके समाधान का तार्किक और वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि जीवन में घटित प्रत्येक घटना कारणद्वारा कार्य संबंधों से जुड़ी होती है तथा अज्ञान और तृष्णा ही दुःख के मूल कारण हैं।

दार्शनिक दृष्टि से यह सिद्धांत यथार्थवाद, मध्यम मार्ग एवं शून्यवाद की आधारशिला प्रस्तुत करता है, जबकि शैक्षिक दृष्टि से यह शिक्षा को तार्किक, वैज्ञानिक, नैतिक एवं जीवनोपयोगी बनाता है। यह विद्यार्थियों में चिंतनशीलता, आत्मविश्लेषण, नैतिकता तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि प्रतीत्य समुत्पाद केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन-दृष्टि है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। वर्तमान समय में, जब शिक्षा को मूल्यपरक एवं व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है, तब यह सिद्धांत शिक्षणदृष्टिगत प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, सार्थक एवं मानवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ

1. त्रिपिटक – बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ।
2. मज्झिम निकाय – पाली साहित्य का प्रमुख स्रोत।
3. संयुक्त निकाय – बौद्ध उपदेशों का संग्रह।
4. दीघ निकाय – दीर्घ उपदेशों का संकलन।
5. अभिधर्म कोश – वसुबंधु कृत।
6. नागार्जुन – माध्यमिक कारिका।
7. बुद्धघोष – विशुद्धिमग्ग
8. गौतम बुद्ध – बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एवं उपदेशक।
9. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन – भारतीय दर्शन।
10. डॉ. एस.एन. दासगुप्ता – History of Indian Philosophy।

समकालीन शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का क्षरण : कारण, प्रभाव एवं समाधान

डॉ. रामानन्द तिवारी¹

1. उत्कर्ष फाउण्डेशन, गोण्डा

सार

समकालीन शिक्षा प्रणाली तीव्र सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रभाव में निरंतर परिवर्तनशील है। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न होकर व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक विकास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के बोध को विकसित करना भी है। किंतु वर्तमान परिदृश्य में यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का निरंतर क्षरण हो रहा है। प्रतिस्पर्धा-प्रधान शिक्षा, उपभोक्तावाद, शिक्षा का व्यवसायीकरण, डिजिटल एवं सोशल मीडिया का प्रभाव तथा परिवार और समाज की बदलती संरचना ने मूल्य-आधारित शिक्षा को हाशिए पर धकेल दिया है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य समकालीन शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों के क्षरण के प्रमुख कारणों की पहचान करना, इसके विद्यार्थियों, समाज एवं राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना तथा इस संकट से उबरने हेतु व्यावहारिक एवं नीतिगत समाधानों का सुझाव देना है। यह अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें शैक्षिक दार्शनिकों के विचारों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तथा पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मूल्य-विहीन शिक्षा के कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, असहिष्णुता, नैतिक निर्णय क्षमता की कमी तथा केवल भौतिक सफलता पर केंद्रित दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। समाज में सामाजिक विघटन, आपसी अविश्वास और नैतिक पतन की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। शोध निष्कर्ष यह भी दर्शाते हैं कि यदि शिक्षा को मूल्य-आधारित दृष्टिकोण से पुनर्संरचित नहीं किया गया, तो मानवता, सामाजिक संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः शिक्षा में नैतिक मूल्यों का पुनर्स्थापन समय की अनिवार्य आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : नैतिक मूल्य, समकालीन शिक्षा, मूल्य-क्षरण, शिक्षा प्रणाली, नैतिक शिक्षा**भूमिका**

शिक्षा मानव जीवन का आधार स्तंभ है, जो न केवल ज्ञान और कौशल के विकास का माध्यम है, बल्कि व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व के निर्माण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य में विवेक, मूल्यबोध, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा मानवीय संवेदनाओं का विकास होता है। भारतीय शिक्षा परंपरा में शिक्षा को विद्या के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास न होकर चरित्र निर्माण एवं आत्म-विकास रहा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में सत्य, अहिंसा, करुणा, अनुशासन, सेवा, त्याग एवं आत्मसंयम जैसे नैतिक मूल्यों को शिक्षा का मूल तत्व माना गया था। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक एवं शिष्य के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित कर

व्यवहारिक जीवन के माध्यम से नैतिक मूल्यों का संचार किया जाता था। किन्तु समकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के इस मूल उद्देश्य में धीरे-धीरे क्षरण दिखाई देने लगा है। वर्तमान समय में शिक्षा को मुख्यतः रोजगार-उन्मुख, प्रतिस्पर्धात्मक और आर्थिक सफलता से जोड़कर देखा जा रहा है। परीक्षा-केंद्रित व्यवस्था, अंकों की दौड़, कोचिंग संस्कृति तथा शिक्षा का व्यवसायीकरण शिक्षा के नैतिक और मानवीय पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा, अनुशासनहीनता, असहिष्णुता, स्वार्थपरक प्रवृत्तियाँ तथा सामाजिक संवेदनशीलता का अभाव बढ़ता जा रहा है। व्यापक सामाजिक स्तर पर यह प्रवृत्तियाँ भ्रष्टाचार, हिंसा, सामाजिक विघटन और आपसी अविश्वास के रूप में परिलक्षित होती हैं।

यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई है। यदि शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों को पुनः केन्द्रीय स्थान नहीं दिया गया, तो शिक्षा केवल डिग्री और रोजगार का साधन बनकर रह जाएगी, जिससे समाज में संतुलित, जिम्मेदार और नैतिक नागरिकों का निर्माण कठिन हो जाएगा। अतः समकालीन शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों की भूमिका, उनके क्षरण के कारणों एवं समाधान पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता है, जो प्रस्तुत अध्ययन का मूल आधार है।

नैतिक मूल्यों की अवधारणा

नैतिक मूल्य वे सामाजिक एवं मानवीय मानदंड हैं, जो व्यक्ति के आचरण, निर्णय क्षमता तथा सामाजिक व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करते हैं। ये मूल्य व्यक्ति को सही और गलत के बीच भेद करना सिखाते हैं तथा उसके विचार, वाणी और कर्म में संतुलन स्थापित करते हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सहिष्णुता, करुणा, उत्तरदायित्व, परोपकार और मानवता जैसे गुण नैतिक मूल्यों के प्रमुख घटक माने जाते हैं। नैतिक मूल्य न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को अनुशासित करते हैं, बल्कि समाज में सद्भाव, सहयोग और सामाजिक न्याय की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं।

भारतीय दार्शनिक परंपरा में नैतिक मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, “शिक्षा वह है जो चरित्र निर्माण करे,” अर्थात् शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को नैतिक, आत्मनिर्भर और विवेकशील बनाना है। इसी प्रकार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा को नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास से जोड़ते हुए कहा कि मूल्य-विहीन शिक्षा समाज को दिशाहीन बना देती है। इन विचारों से स्पष्ट होता है कि नैतिक मूल्य शिक्षा के मूल में निहित होने चाहिए।

नैतिक मूल्यों का विकास केवल सैद्धांतिक ज्ञान से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव है जब विद्यालयी पाठ्यक्रम में

मूल्य-आधारित विषयों को समुचित स्थान दिया जाए, शिक्षक अपने आचरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत करें, विद्यालयी वातावरण सहयोगात्मक एवं अनुशासित हो तथा परिवार एवं समाज नैतिक मूल्यों के संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाएँ। इस प्रकार पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यवहार, विद्यालयी संस्कृति और सामाजिक परिवेश के समन्वय से ही नैतिक मूल्यों का प्रभावी विकास संभव हो सकता है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली का स्वरूप

वर्तमान शिक्षा प्रणाली वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रियाओं से गहराई से प्रभावित है। इन परिवर्तनों ने शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य और कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव उत्पन्न किए हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने शिक्षा को अधिक सुलभ, बहुआयामी और तकनीक-संपन्न अवश्य बनाया है, किंतु इसके साथ अनेक शैक्षिक एवं नैतिक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। डिजिटल माध्यमों के अत्यधिक प्रयोग ने शिक्षक-विद्यार्थी के प्रत्यक्ष संवाद को सीमित किया है, जिससे शिक्षा का मानवीय पक्ष कमजोर होता जा रहा है।

समकालीन शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख स्वरूप परीक्षा-केन्द्रित शिक्षा है, जिसमें अधिगम की वास्तविक गुणवत्ता के स्थान पर अंकों और परिणामों को अधिक महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन मुख्यतः परीक्षाओं और अंकों के आधार पर किया जाता है, जिससे रचनात्मकता, नैतिक संवेदनशीलता एवं समग्र विकास की उपेक्षा होती है। इसी के साथ अंक एवं रैंक आधारित प्रतिस्पर्धा ने विद्यार्थियों में तनाव, असहिष्णुता और स्वार्थपरक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है।

कोचिंग संस्कृति का तेजी से विस्तार शिक्षा को यांत्रिक और बाजार-आधारित बना रहा है। विद्यालयों की भूमिका सीमित होती जा रही है और शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने तक सिमटती जा रही है। इसके अतिरिक्त शिक्षा का व्यवसायीकरण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है, जहाँ ज्ञान के

स्थान पर लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है। निजी शिक्षण संस्थानों में नैतिक और सामाजिक उद्देश्यों की अपेक्षा आर्थिक हितों को अधिक महत्व दिया जाता है।

इन सभी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप शिक्षक-विद्यार्थी संबंधों में भी औपचारिकता आ गई है। शिक्षक मार्गदर्शक और नैतिक आदर्श की भूमिका से हटकर केवल विषय-वस्तु तक सीमित होते जा रहे हैं। इस प्रकार समकालीन शिक्षा प्रणाली का यह स्वरूप शिक्षा के मानवीय, नैतिक एवं मूल्यपरक पक्ष को कमजोर कर रहा है, जो समाज और राष्ट्र के लिए चिंताजनक संकेत है।

नैतिक मूल्यों के क्षरण के प्रमुख कारण

नैतिक मूल्यों के क्षरण के प्रमुख कारण

1. शिक्षा का व्यवसायीकरण

समकालीन शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों के क्षरण का एक प्रमुख कारण शिक्षा का तीव्र व्यवसायीकरण है। निजी शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या ने शिक्षा को सेवा के बजाय उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया है। इन संस्थानों में ज्ञान और चरित्र निर्माण की अपेक्षा लाभ, ब्रांडिंग और प्रतिस्पर्धा को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। परिणामस्वरूप शिक्षा के मूल नैतिक उद्देश्य गौण हो गए हैं और विद्यार्थियों को उपभोक्ता के रूप में देखा जाने लगा है। यह प्रवृत्ति शिक्षा के मानवीय और मूल्यपरक स्वरूप को कमजोर करती है।

2. परिवार व्यवस्था में परिवर्तन

परिवार नैतिक मूल्यों के विकास की प्रथम और महत्वपूर्ण इकाई है। किंतु वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों का विघटन, एकल परिवारों की बढ़ती संख्या, माता-पिता का कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहना तथा बच्चों के लिए समय की कमी ने नैतिक संस्कारों के विकास को प्रभावित किया है। जब परिवार स्तर पर मूल्य-बोध कमजोर होता है, तो

विद्यालय अकेले नैतिक विकास की जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा नहीं पाता।

3. पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा की उपेक्षा

विद्यालयी पाठ्यक्रम में नैतिक एवं मूल्य शिक्षा को सीमित स्थान दिया गया है। अधिकांशतः यह शिक्षा सैद्धांतिक एवं औपचारिक बनकर रह गई है, जिसका विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से सीधा संबंध नहीं बन पाता। गतिविधि-आधारित, अनुभवात्मक एवं व्यवहारिक मूल्य शिक्षा के अभाव में विद्यार्थी नैतिक सिद्धांतों को व्यवहार में नहीं अपना पाते, जिससे मूल्य-क्षरण की स्थिति उत्पन्न होती है।

4. डिजिटल एवं सोशल मीडिया का प्रभाव

डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया ने बच्चों और युवाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। अनियंत्रित इंटरनेट उपयोग, हिंसक, भौतिकवादी एवं उपभोक्तावादी सामग्री की अधिकता ने विद्यार्थियों के आचरण, भाषा और सोच पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। आभासी संसार में समय बिताने से सामाजिक संवेदनशीलता, सहानुभूति और नैतिक विवेक का विकास बाधित हो रहा है।

5. नैतिक आदर्शों का अभाव

राजनीति, प्रशासन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक आदर्शों की कमी भी नैतिक मूल्यों के क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनैतिक आचरण दिखाई देता है, तो विद्यार्थी भी इन्हीं प्रवृत्तियों को सामान्य मानने लगते हैं। आदर्श व्यक्तित्वों और सकारात्मक रोल मॉडल्स के अभाव में नैतिक मूल्यों का प्रभावी संचार संभव नहीं हो पाता।

नैतिक मूल्यों के क्षरण के प्रभाव

1. विद्यार्थियों पर प्रभाव

नैतिक मूल्यों के क्षरण का सबसे प्रत्यक्ष और गहरा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। मूल्य-विहीन शिक्षा के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे विद्यालयी वातावरण अव्यवस्थित होता है। असहिष्णुता और आक्रामकता जैसी प्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों के व्यवहार में परिलक्षित होने लगती हैं, जिससे आपसी सहयोग और सह-अस्तित्व की भावना कमजोर होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता, अधिक आय और सामाजिक प्रतिष्ठा तक सीमित हो जाता है। इस भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण नैतिकता, सेवा भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों की उपेक्षा होने लगती है, जो विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास में बाधक सिद्ध होती है।

2. समाज पर प्रभाव

जब शिक्षा प्रणाली नैतिक मूल्यों का संवर्धन नहीं कर पाती, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समाज में सामाजिक विघटन, पारिवारिक अस्थिरता और आपसी संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। नैतिक मूल्यों के अभाव में अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा और अनैतिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जाती है। इसके साथ ही समाज में आपसी विश्वास और सामाजिक सहयोग की भावना कमजोर पड़ जाती है, जिससे सामूहिक विकास और सामाजिक समरसता बाधित होती है।

3. राष्ट्र पर प्रभाव

नैतिक मूल्यों के क्षरण का दीर्घकालिक और व्यापक प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता है। मूल्य-विहीन शिक्षा जिम्मेदार, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के निर्माण में

असफल रहती है। इसके परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक आदर्शों और राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नागरिकों में कानून के प्रति सम्मान, सामाजिक न्याय और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना कमजोर होने लगती है। यह स्थिति अंततः सामाजिक एवं नैतिक संकट को जन्म देती है, जो किसी भी राष्ट्र की प्रगति और स्थायित्व के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नैतिक मूल्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा व्यवस्था को केवल ज्ञान और कौशल तक सीमित न रखकर उसे नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों से युक्त समग्र शिक्षा के रूप में विकसित करने का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह नीति यह स्वीकार करती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार सृजन नहीं, बल्कि संवेदनशील, जिम्मेदार, नैतिक एवं राष्ट्रनिष्ठ नागरिकों का निर्माण भी है।

NEP 2020 में मूल्य-आधारित शिक्षा को शिक्षा के प्रत्येक स्तर प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का अभिन्न अंग माना गया है। नीति में सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, सहयोग, ईमानदारी, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक चेतना तथा संवैधानिक मूल्यों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत संविधान की मूल भावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता को शैक्षिक पाठ्यक्रम का आधार बनाने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System) को पुनर्स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उपनिषदों, वेदों, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सूफी परंपरा और भारतीय संत परंपरा में निहित नैतिक मूल्यों को आधुनिक संदर्भों से जोड़कर प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों में सांस्कृतिक गर्व,

नैतिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हो सके।

नीति में जीवन कौशल (Life Skills), जैसे—आत्मानुशासन, निर्णय क्षमता, सहानुभूति, संघर्ष समाधान, नेतृत्व और सहयोगात्मक व्यवहार को शिक्षा का अनिवार्य घटक माना गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नैतिक शिक्षा को केवल सैद्धांतिक विषय न मानकर व्यवहारिक और अनुभवात्मक अधिगम के माध्यम से विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

NEP 2020 में शिक्षक की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षक को केवल विषयवस्तु का संप्रेषक न मानकर मार्गदर्शक, प्रेरक एवं नैतिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षक—प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नैतिकता, व्यावसायिक आचरण और मानवीय संवेदनशीलता को अनिवार्य रूप से शामिल करने की अनुशंसा की गई है। यह दृष्टिकोण नैतिक मूल्यों के पुनरुत्थान की दिशा में एक सकारात्मक और व्यावहारिक संकेत प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, नीति में बहुविषयक शिक्षा, समावेशी वातावरण, समान अवसर, सामाजिक सहभागिता और सेवा आधारित अधिगम (Service Learning) को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे विद्यार्थी समाज से जुड़कर नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात कर सकें।

इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समकालीन शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों के क्षरण की समस्या को स्वीकार करते हुए उसके समाधान हेतु संरचनात्मक, पाठ्यक्रमीय और व्यवहारिक स्तर पर ठोस प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि नीति के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, तो शिक्षा को पुनः उसके मानवीय, नैतिक और सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा जा सकता है।

7. नैतिक मूल्यों के पुनर्स्थापन हेतु समाधान

समकालीन शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों के क्षरण की समस्या केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इस संकट

से उबरने के लिए शिक्षा के विभिन्न घटकों—कृपाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालयी वातावरण, परिवार, समाज तथा डिजिटल माध्यमों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। निम्नलिखित समाधान इस दिशा में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं—

1. पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा का समावेश

पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को केवल एक सैद्धांतिक विषय के रूप में न रखकर उसे व्यवहारिक, अनुभवात्मक और गतिविधि—आधारित बनाया जाना चाहिए। कहानी—वाचन, नाटक, समूह—चर्चा, परियोजना कार्य, सेवा—अधिगम (मतअपबम स्मंतदपदह) तथा जीवन—परिस्थितियों पर आधारित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, सहयोग, जिम्मेदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विकास किया जा सकता है। मूल्य शिक्षा को सभी विषयों के साथ अंतःविषय रूप में जोड़ा जाना अधिक प्रभावी होगा।

2. शिक्षक की भूमिका

नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका केन्द्रीय है। शिक्षक को केवल विषय—विशेषज्ञ तक सीमित न रखते हुए नैतिक आदर्श, प्रेरक एवं मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उनका आचरण, व्यवहार, भाषा और निर्णय विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण बनते हैं। अतः शिक्षक—प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक आचार—संहिता, मानवीय संवेदनशीलता और मूल्य—आधारित शिक्षण पद्धतियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

3. विद्यालयी वातावरण

विद्यालयी वातावरण का नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय में सहयोग, अनुशासन, परस्पर सम्मान, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली संस्कृति विकसित की जानी चाहिए। छात्र—परिषद, सामूहिक

निर्णय-प्रक्रिया, सहशैक्षिक गतिविधियाँ और निष्कर्ष

सामाजिक सेवा कार्यक्रम विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप से नैतिक मूल्यों को अपनाने का अवसर प्रदान करते हैं। भय-आधारित अनुशासन के स्थान पर संवाद और सहभागिता पर आधारित अनुशासन प्रणाली अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

4. परिवार और समाज की सहभागिता

नैतिक शिक्षा केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार और समाज का सहयोग इसके लिए अनिवार्य है। अभिभावकों को बच्चों के नैतिक विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तथा विद्यालय के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए। समाज में सकारात्मक आदर्श, नैतिक नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। विद्यालय-समुदाय साझेदारी से नैतिक मूल्यों का स्थायी विकास संभव है।

5. डिजिटल साक्षरता और नैतिक नियंत्रण

डिजिटल युग में नैतिक शिक्षा का दायरा डिजिटल माध्यमों तक विस्तारित करना आवश्यक है। विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता, साइबर नैतिकता, मीडिया विवेक और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार का विकास किया जाना चाहिए। डिजिटल माध्यमों के सकारात्मक, रचनात्मक और शैक्षणिक उपयोग पर बल देते हुए उनके दुरुपयोग से बचाव हेतु नैतिक नियंत्रण और मार्गदर्शन आवश्यक है। इससे तकनीक शिक्षा का साधन बनेगी, न कि नैतिक पतन का कारण।

उपरोक्त समाधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षा को पुनः उसके मानवीय, नैतिक और सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा जा सकता है। नैतिक मूल्यों का पुनर्स्थापन तभी संभव है जब शिक्षा प्रणाली के सभी घटक सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व निभाएँ।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि समकालीन शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का क्षरण एक गम्भीर एवं बहुआयामी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इस क्षरण का प्रभाव केवल विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव समाज की संरचना, सामाजिक सौहार्द, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय चरित्र पर भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। जब शिक्षा का लक्ष्य केवल अंक, रैंक, प्रतिस्पर्धा और रोजगार तक सीमित हो जाता है, तब उसमें निहित मानवीय संवेदना, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक चेतना क्रमशः कमजोर होती जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा मानव निर्माण के स्थान पर मात्र आर्थिक उत्पादन का साधन बनकर रह जाती है, जो दीर्घकाल में मानवता और सामाजिक संतुलन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।

अध्ययन यह संकेत देता है कि नैतिक मूल्यों का विकास किसी एक घटक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालयी वातावरण, परिवार, समाज तथा डिजिटल संस्कृति के समन्वित प्रयासों से ही संभव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को समग्र, समावेशी एवं मूल्य-आधारित बनाने की दिशा में एक सशक्त और सकारात्मक पहल प्रस्तुत करती है। नीति में नैतिकता, संवैधानिक मूल्य, भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन कौशल और चरित्र निर्माण पर दिया गया बल समकालीन शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

हालाँकि, नीति की सफलता केवल उसके घोषणात्मक स्वरूप पर नहीं, बल्कि उसके प्रभावी एवं व्यावहारिक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक नैतिक आदर्श के रूप में कार्य करें, विद्यालय मूल्य-आधारित संस्कृति विकसित करें, अभिभावक बच्चों के संस्कार निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएँ, समाज सकारात्मक आदर्श प्रस्तुत करे तथा नीति-निर्माता शिक्षा को व्यवसाय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम मानें।

अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों का पुनर्स्थापन समय की अनिवार्य आवश्यकता है। मूल्य-आधारित, मानव-केंद्रित और समग्र शिक्षा ही ऐसे उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण कर सकती है, जो न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हों, बल्कि नैतिक, सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी सशक्त राष्ट्र की आधारशिला रख सकें।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकारण (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई दिल्ली— शिक्षा मंत्रालय।
2. राधाकृष्णनए डॉ. एस. (1965) भारतीय शिक्षाण नई दिल्ली— ओरिएंट लॉन्गमैन।
3. विवेकानंद, स्वामी, (2008) शिक्षा पर विचारण अद्वैत आश्रम।
4. NCERT (2005) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नई दिल्ली।
5. गांधी, मोहनदास करमचंद, (2010) बुनियादी शिक्षा. अहमदाबाद— नवजीवन प्रकाशन।
- 6- यूनेस्को (2015) Rethinking Education: Towards a Global Common Good, पेरिस— UNESCO Publishing.
7. यादव, एस. (2018) शिक्षा और नैतिक मूल्य, नई दिल्ली— ओरिएंट ब्लैकस्वान।
8. शर्मा, आर. के. (2016), शिक्षा का समाजशास्त्र, मेरठ— राधा प्रकाशन।
9. कुमार, एन. (2019), समकालीन शिक्षा में मूल्यों का संकट, भारतीय शैक्षिक शोध पत्रिका, 8(2), 45–52।

वैश्विक-मानक संस्थाओं का विकास : एन0ई0पी0 2020 के सन्दर्भ में

डॉ० मनिक मोहन शुक्ल¹

विभागाध्यक्ष, बी0एड0 विभाग, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, बोधगया, बिहार।

सारांश

वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक शिक्षा प्रणाली को नए आयाम दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा में वैश्विक-मानक संस्थाओं की आवश्यकता और महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। ऐसी संस्थाएँ न केवल उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करती हैं, बल्कि आधुनिक अवसंरचना, प्रगतिशील प्रशासनिक प्रथाएँ, और नवाचारपूर्ण शिक्षण विधियों को भी अपनाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 इस दिशा में एक दूरदर्शी नीति के रूप में सामने आई है, जो भारत में विश्व-स्तरीय संस्थानों के निर्माण और विकास पर विशेष बल देती है।

NEP 2020 का उद्देश्य केवल आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ भारतीय सांस्कृतिक और ज्ञान परंपराओं, मूल्य-आधारित शिक्षा, और समग्र मानव विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना है। नीति बहुविषयक शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और नवाचार, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी एकीकरण, और सतत विकास जैसे प्रमुख पहलुओं पर जोर देती है।

यह शोधपत्र वैश्विक-मानक संस्थाओं के लक्षण, उनके रणनीतिक ढांचे, विकास के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय, संभावित चुनौतियाँ, और उपलब्ध अवसरों का विश्लेषण करता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे NEP 2020 के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा और वैश्विक सहयोग के माध्यम से भारत को एक ज्ञान-संचालित वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि वैश्विक-मानक संस्थाओं का निर्माण न केवल भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, बल्कि विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर सक्षम, नैतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने में भी सहायक होगा।

मुख्य शब्द— वैश्विक-मानक संस्थाएँ, NEP 2020, अंतरराष्ट्रीयकरण, भारतीय ज्ञान प्रणाली, उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार

परिचय

वैश्वीकरण ने उच्च शिक्षा के परिदृश्य को गहराई से बदल दिया है। आज की दुनिया में शिक्षा केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसे वैश्विक मानकों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप होना आवश्यक हो गया है। इस बदलाव ने ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता को बढ़ा दिया है, जो न केवल उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और शोध प्रदान करें, बल्कि आधुनिक अवसंरचना, उन्नत शिक्षण पद्धतियाँ और प्रशासनिक उत्कृष्टता भी सुनिश्चित करें।

वैश्विक-मानक संस्थाएँ बहुविषयक शिक्षा, शोध और नवाचार के अवसर प्रदान करती हैं। ये संस्थाएँ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए स्थानीय सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को संरक्षित करती हैं। इस प्रकार, छात्रों को न केवल ज्ञान और कौशल में प्रवीण बनाया जाता है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से जिम्मेदार और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नागरिक के रूप में भी तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 इस आवश्यकता को स्पष्ट रूप से मानती है और भारत में विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के निर्माण पर विशेष बल देती है। नीति का उद्देश्य है कि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बने, अंतरराष्ट्रीय

छात्रों और विद्वानों को आकर्षित कर सके, और एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। NEP 2020 बहुविषयक दृष्टिकोण, अनुसंधान और नवाचार, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी एकीकरण, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर देती है।

नीति के तहत शिक्षा संस्थानों को विश्व-स्तरीय बनने के लिए कई प्रमुख उपाय सुझाए गए हैं, जैसे कि बहुविषयक पाठ्यक्रम का विकास, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना, शिक्षक क्षमता निर्माण, डिजिटल शिक्षण के संसाधनों का समुचित उपयोग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इन उपायों के माध्यम से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को न केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और ज्ञान परंपराओं का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

इस प्रकार, वैश्विक-मानक संस्थाओं का विकास केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास, अंतरराष्ट्रीय पहचान और ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी सहायक है। NEP 2020 के दिशा-निर्देश इस दिशा में स्पष्ट और दूरदर्शी रूपरेखा प्रदान करते हैं।

वैश्विक-मानक संस्थाओं के लक्षण

वैश्विक-मानक संस्थाएँ निम्नलिखित विशेषताओं से पहचानी जाती हैं—

1. **बहुविषयक और समग्र शिक्षा**— कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करके छात्रों में अंतरविषयक कौशल विकसित करना।
2. **उच्च-गुणवत्ता वाले शिक्षक और नेतृत्व**— अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले योग्य शिक्षक और नेतृत्व विकास कार्यक्रम।
3. **आधुनिक अवसंरचना**— स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएँ, डिजिटल पुस्तकालय और अत्याधुनिक संसाधन।
4. **शोध और नवाचार केंद्र**— उद्योग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।

5. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग**— विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी, छात्र और शिक्षक विनिमय, और संयुक्त पाठ्यक्रम विकास।
6. **वैश्विक मान्यता**— अंतरराष्ट्रीय मान्यता और मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
7. **भारतीय ज्ञान प्रणाली का समावेश**— भारतीय दर्शन, संस्कृति और परंपराओं को शिक्षा में शामिल करना।
8. **डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा**— ई-लर्निंग, वर्चुअल लैब और डिजिटल पुस्तकालयों का उपयोग।
9. **छात्र-केंद्रित शिक्षण**— अनुभवात्मक, दक्षता-आधारित और समग्र विकास पर जोर।
10. **सतत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी**— नैतिक प्रथाओं, पर्यावरणीय स्थिरता और समाज सेवा को संस्थागत गतिविधियों में शामिल करना।

NEP 2020 के तहत रणनीतिक ढांचा

वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संस्थानों का रणनीतिक रूप से पुनर्गठन आवश्यक है। NEP 2020 इस दिशा में स्पष्ट ढांचा प्रस्तुत करती है, जिसमें बहुविषयक शिक्षा, शोध एवं नवाचार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी एकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन पर विशेष बल दिया गया है। इस ढांचे का उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पेशेवर और ज्ञान-संचालित बनाना है।

1. संस्थानिक पुनर्गठन

स्वतंत्र महाविद्यालयों का एकीकरण कर बहुविषयक विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य संसाधनों का कुशल उपयोग, बहुविषयक शिक्षा का विकास और विद्यार्थियों को व्यापक अध्ययन के अवसर प्रदान करना है।

2. शोध और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र

अनुसंधान पार्क, इनक्यूबेटर और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संस्थानों में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कदम उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और नए ज्ञान का सृजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

3. क्षमता निर्माण

शिक्षक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, तकनीकी उपकरणों और नवाचारों के साथ दक्ष हों।

4. अंतरराष्ट्रीयकरण

शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल भारतीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा, बल्कि छात्रों और शिक्षकों को वैश्विक अनुभव और नेटवर्किंग के अवसर भी मिलेंगे।

5. तकनीकी एकीकरण

डिजिटल कक्षाओं, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और ई-शिक्षण संसाधनों के उपयोग से शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को आधुनिक और सुलभ बनाया जाएगा। यह कदम शिक्षा को समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त करने में सहायक होगा।

6. गुणवत्ता सुनिश्चित करना

आंतरिक और बाहरी गुणवत्ता आश्वासन, मान्यता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाकर संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इससे छात्रों को विश्वसनीय और मान्यता प्राप्त डिग्रियाँ प्राप्त होंगी।

इस प्रकार प्रस्तुत रणनीतिक ढांचा भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप

तैयार करने, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने, शिक्षक और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने, तकनीकी एकीकरण करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन करता है। NEP 2020 के तहत यह ढांचा भारत को शिक्षा और ज्ञान-सृजन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

वैश्विक-मानक संस्थाओं के विकास में चुनौतियाँ

वैश्विक-मानक संस्थाओं के निर्माण और विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, शोध और प्रशासनिक दक्षता आवश्यक है। हालांकि, इस दिशा में कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिन्हें पहचानना और उनका समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1. संसाधन सीमाएँ

आधुनिक अवसंरचना, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, डिजिटल कक्षाएँ और शोध सुविधाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधनों की कमी संस्थागत विकास को धीमा कर सकती है।

2. शिक्षक और शोधकर्ता की कमी

योग्य और अनुभवी शिक्षक तथा शोधकर्ताओं की कमी, वैश्विक स्तर की शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों को प्रभावित करती है। संस्थानों को विशेषज्ञ कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

3. परंपरागत प्रतिरोध

पारंपरिक शिक्षण और प्रशासनिक पद्धतियों में बदलाव के प्रति प्रतिरोध, नवाचार और आधुनिक शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा डाल सकता है।

4. नीति और शासन

प्रभावी नीति कार्यान्वयन, संस्थागत स्वायत्तता और शासन संरचना की कमी, संस्थाओं के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बाधा उत्पन्न करती है।

5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा

अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से छात्रों, शिक्षकों और निवेश के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा, भारतीय संस्थानों के लिए चुनौतियाँ पैदा करती है। उच्च गुणवत्ता और वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

इन चुनौतियों को पहचानकर और रणनीतिक उपायों के माध्यम से उनका समाधान करके ही भारत में वैश्विक-मानक संस्थाओं का सफल विकास संभव है। संसाधन सृजन, क्षमता निर्माण, नीति सुधार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अवसर और लाभ

वैश्विक-मानक संस्थाओं के विकास के साथ कई अवसर और लाभ जुड़े हैं, जो न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को भी सुदृढ़ करते हैं।

1. भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करना

उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, शोध और नवाचार के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. अंतरराष्ट्रीय स्तर के योग्य स्नातक तैयार करना

वैश्विक-मानक संस्थाओं में बहुविषयक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के अवसरों के माध्यम से विद्यार्थी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होते हैं।

3. बहुविषयक शोध और नवाचार को बढ़ावा देना

संस्थाओं में अनुसंधान पार्क, इनक्यूबेटर और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बहुविषयक शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है।

4. अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करना

वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा और आधुनिक संसाधनों के कारण भारत के

विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।

5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना

वैश्विक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्य संरक्षित रहते हैं, जिससे शिक्षा का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित होता है।

इन अवसरों और लाभों का प्रभावी उपयोग करके भारत न केवल शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकता है, बल्कि राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक मूल्यों और अनुसंधान क्षमता को भी सुदृढ़ कर सकता है।

6. निष्कर्ष

वैश्विक-मानक संस्थाओं का विकास आज भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना है, बल्कि छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता भी है। इस संदर्भ में NEP 2020 एक स्पष्ट और दूरदर्शी रणनीति प्रस्तुत करती है, जो बहुविषयक शिक्षा, शोध और नवाचार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल शिक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों के संतुलन पर आधारित है। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार हों, और छात्रों को आवश्यक कौशल, ज्ञान और नवाचार की क्षमता प्रदान की जा सके।

नीति के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे संसाधनों की सीमाएँ, योग्य शिक्षक और शोधकर्ताओं की कमी, पारंपरिक शिक्षण और प्रशासनिक पद्धतियों में प्रतिरोध, नीति और शासन से जुड़े मुद्दे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। इन चुनौतियों के बावजूद, NEP 2020 के माध्यम से प्रस्तावित बहुविषयक दृष्टिकोण, शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और

डिजिटल संसाधनों का समुचित उपयोग, भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक साबित हो सकते हैं।

साथ ही, नीति भारतीय सांस्कृतिक, नैतिक और ज्ञान परंपराओं को संरक्षित रखते हुए वैश्विक शिक्षा के सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर बल देती है। इसका अर्थ यह है कि छात्र और शिक्षक न केवल तकनीकी और अकादमिक दक्षता में प्रवीण होंगे, बल्कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान और मूल्यों को भी बनाए रखेंगे। इस संतुलित दृष्टिकोण से भारत न केवल विश्व-स्तरीय संस्थानों का निर्माण कर सकेगा, बल्कि ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए सक्षम और जिम्मेदार वैश्विक नागरिक तैयार कर सकेगा।

अतः यह कहा जा सकता है कि वैश्विक-मानक संस्थाओं का विकास और NEP 2020 के तहत उनकी रणनीतिक रूपरेखा, भारत को उच्च शिक्षा में वैश्विक नेतृत्व दिलाने, अंतरराष्ट्रीय छात्रों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने और राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

सुझाव और रणनीतियाँ

वैश्विक-मानक संस्थाओं के विकास के लिए केवल नीति का होना पर्याप्त नहीं है। इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना आवश्यक है। इसके लिए निम्न रणनीतिक उपाय और समर्थनकारी कदम उठाना अनिवार्य हैं।

1. अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना

शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ भागीदारी, संयुक्त शोध, पाठ्यक्रम विकास और शिक्षकध्विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रम बढ़ाने चाहिए।

2. शिक्षक और शोधकर्ता क्षमता निर्माण

नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ और पेशेवर विकास कार्यक्रम आयोजित करके शिक्षकों और शोधकर्ताओं की वैश्विक कौशल क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए।

3. अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना संस्थानों में अनुसंधान पार्क, इनक्यूबेटर और प्रयोगात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे बहुविषयक और नवाचार-आधारित शिक्षा सुनिश्चित होगी।

4. डिजिटल शिक्षा और तकनीकी अपनाना

ई-शिक्षण संसाधनों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल कक्षाओं का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए। यह शिक्षा को समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त करने में सहायक होगा।

5. नीति और प्रशासनिक सुधार

प्रभावी नीति कार्यान्वयन और संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे निर्णय लेने की गति बढ़ेगी और संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

6. संसाधन और वित्तीय समर्थन

आधुनिक अवसंरचना, प्रयोगशालाएँ और शोध सुविधाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

7. भारतीय सांस्कृतिक और ज्ञान मूल्यों का समन्वय

वैश्विक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शिक्षा का संतुलित विकास सुनिश्चित हो।

इन सुझावों और रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से भारत में वैश्विक-मानक संस्थाओं का निर्माण और संचालन संभव होगा। यह कदम न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक कौशल को भी सुदृढ़ करेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. भारत सरकार, (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE), (2021), शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचा। नई दिल्ली– NCTE।
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)। (2023)। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, नई दिल्ली– NCERT।
4. यूनेस्को, (2015), वैश्विक नागरिक शिक्षा– 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए शिक्षार्थियों की तैयारी। पेरिस– यूनेस्को।
5. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, (2021), NEP 2020 कार्यान्वयन दिशानिर्देश– शिक्षक शिक्षा, नई दिल्ली।
6. राव, के. एल, (2021), भारत में शिक्षक शिक्षा, NEP 2020 के तहत चुनौतियाँ और अवसर। नई दिल्ली– सेज पब्लिकेशन।
7. तिलक, जे. बी. जी, (2020), भारत में शिक्षा और विकास नीति और अभ्यास, नई दिल्ली– ओरिएंट ब्लैकस्वान।
8. शर्मा, आर., एवं सिंह, पी, (2022), वैश्विक दक्षता और शिक्षक शिक्षा– भारतीय ज्ञान प्रणाली का समन्वय। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान पत्रिका, 10(2), 45–60।
9. चौधरी, एस, (2021), भारतीय शिक्षक शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण–NEP 2020 का दृष्टिकोण, शिक्षक शिक्षा और अनुसंधान पत्रिका, 16(1), 12–28।
10. पाटिल, एम., एवं देशमुख, एस, (2021), शिक्षक शिक्षा में डिजिटल और समग्र शिक्षण–NEP 2020 दृष्टिकोण, शैक्षिक नवाचार पत्रिका, 8(3), 75–88।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वैदिक शिक्षा के संदर्भ में विश्लेषण

(An Analysis of National Education Policy 2020 in the Context of Vedic Education)

प्रो० डॉ० श्री प्रकाश मिश्र

आचार्य, बी०एड विभाग, महारानी लाल कुँवर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलरामपुर

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान प्रणाली से जोड़ते हुए 21वीं सदी की वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है। यह नीति केवल आधुनिक तकनीकी और अकादमिक दक्षताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के समन्वय पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। भारतीय शिक्षा की प्राचीनतम परंपरा, अर्थात् वैदिक शिक्षा, नैतिकता, आत्मबोध, गुरु-शिष्य परंपरा, योग, ध्यान और समग्र व्यक्तित्व विकास पर आधारित रही है।

इस शोध-पत्र में NEP 2020 का वैदिक शिक्षा के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नीति में वैदिक शिक्षा की मूल धारणाओं जैसे जीवनोपयोगी कौशल, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास, योग और ध्यान, संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपराकृत आधुनिक पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली में समाहित करने के प्रयास किए गए हैं। नीति शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन का माध्यम न मानकर, इसे सामाजिक और नैतिक चेतना विकसित करने का एक प्रभावी उपकरण बनाती है। साथ ही, यह शिक्षा नीति गुरु-शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करने और शिक्षकों को मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है। यह नीति परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करती है, जिससे छात्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। शोध निष्कर्ष के अनुसार, NEP 2020 वैदिक शिक्षा की पुनर्प्रतिष्ठा की दिशा में न केवल सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है, बल्कि उसे व्यवहारिक और पाठ्यक्रमगत रूप में लागू करने की रणनीति भी प्रस्तुत करती है।

मुख्य शब्द— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वैदिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, नैतिक मूल्य, समग्र विकास

भूमिका

भारतीय शिक्षा परंपरा का मूल वैदिक काल में निहित है, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका अर्जन नहीं, बल्कि जीवन के चार पुरुषार्थकृधर्म, अर्थ, काम और मोक्षकृकी प्राप्ति था। वैदिक शिक्षा प्रणाली ने व्यक्ति के नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास को समान महत्व दिया। इसके अंतर्गत गुरु-शिष्य परंपरा, चरित्र निर्माण, आत्मबोध, योग और ध्यान, जीवनोपयोगी कौशल तथा सामाजिक जिम्मेदारी का समन्वय निहित था। शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन जीने की कला, सामाजिक जीवन में न्याय एवं करुणा का मार्ग और व्यक्तित्व के समग्र विकास का माध्यम थी।

औपनिवेशिक काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ा, जिससे शिक्षा

का स्वरूप अधिगम आधारित और प्रतियोगिता केंद्रित

हो गया। इस दौरान भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत साहित्य, योग और नैतिक शिक्षा हाशिये पर चली गई। भारतीय शिक्षा ने अपनी सांस्कृतिक आत्मा और जीवनोपयोगी मूल्यों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी ऐतिहासिक विच्छेदन को समाप्त करने का एक प्रयास है। यह नीति न केवल आधुनिक तकनीकी और अकादमिक कौशलों पर ध्यान देती है, बल्कि शिक्षा को भारतीय मूल्यों, ज्ञान परंपरा और संस्कृति से जोड़कर समग्र विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। NEP 2020 में योग, ध्यान, नैतिक शिक्षा, संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान प्रणाली को विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इस प्रकार यह नीति वैदिक शिक्षा के आदर्शों और

आधुनिक शिक्षा के आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन स्थापित करती है, जो छात्रों को ज्ञान, मूल्य और कौशलों के समन्वित विकास की दिशा में अग्रसर करती है।

वैदिक शिक्षा प्रणाली : एक संक्षिप्त परिचय

वैदिक शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की प्राचीनतम और प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली रही है। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना था। वैदिक शिक्षा में छात्र का नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था।

1. गुरुकुल व्यवस्था

गुरुकुल व्यवस्था वैदिक शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। इस प्रणाली में शिक्षा का केंद्र गुरु और शिष्य के बीच का गहन और आत्मीय संबंध होता था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहते और जीवन की सभी गतिविधियों में उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते। यहाँ शिक्षा केवल शैक्षिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों का अभ्यास भी इसका अभिन्न अंग था। गुरु शिष्य के जीवन के हर पहलू में उसे मार्गदर्शन देते थे और उसके व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होते थे। इस प्रकार, गुरुकुल न केवल अध्ययन का केंद्र था, बल्कि जीवन जीने की कला और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाने का माध्यम भी था।

2. चरित्र निर्माण

वैदिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। सत्य, अहिंसा, संयम, ब्रह्मचर्य, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे आदर्श शिक्षा के मुख्य स्तंभ थे। विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान नहीं सिखाया जाता था, बल्कि व्यवहार में नैतिकता और आत्म-अनुशासन का पालन

करना भी सिखाया जाता था। यह दृष्टिकोण आज की आधुनिक शिक्षा के नैतिक-सामाजिक विकास पर आधारित पाठ्यक्रमों से मेल खाता है।

3. समग्र विकास

वैदिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास था। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को समान महत्व दिया गया। शारीरिक शिक्षा, योग और ध्यान के माध्यम से शरीर और मन का संतुलन बनाए रखा जाता था। बौद्धिक विकास के लिए वेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। साथ ही, शिक्षा का आध्यात्मिक पक्ष विद्यार्थियों को आत्मबोध और जीवन के उच्चतर उद्देश्य से परिचित कराता था।

4. ज्ञान का व्यावहारिक स्वरूप

वैदिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका व्यावहारिक और जीवनोपयोगी स्वरूप था। शिक्षा केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी बल्कि विद्यार्थियों को अपने अध्ययन का वास्तविक जीवन में उपयोग करना सिखाया जाता था। कृषि, व्यापार, चिकित्सा, खगोलशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे क्षेत्रों में ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रयोग कराया जाता था। इस प्रकार, शिक्षा विद्यार्थियों को सिद्धांत और व्यवहार के बीच संतुलन सिखाती थी।

5. संस्कृत भाषा का महत्व

संस्कृत वैदिक शिक्षा की मूल भाषा थी और इसे ज्ञान के संचार का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता था। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक इसी भाषा में संरक्षित हैं। संस्कृत भाषा का अध्ययन विद्यार्थियों को विस्तृत दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुँचाने में सक्षम बनाता था। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं था, बल्कि जीवन के

उच्चतम मूल्य और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना था।

वैदिक शिक्षा प्रणाली न केवल ज्ञानार्जन का माध्यम थी, बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण का भी प्रमुख साधन थी। यह आज भी शिक्षा के समग्र और जीवनोपयोगी दृष्टिकोण के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक अवलोकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का दस्तावेज है। इसका उद्देश्य केवल आधुनिक तकनीकी और अकादमिक दक्षताओं को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि शिक्षा को भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना भी है। नीति का दृष्टिकोण शिक्षा को समग्र विकास, नैतिक मूल्यों और जीवनोपयोगी कौशलों के साथ जोड़ने पर आधारित है।

NEP 2020 का प्रमुख उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली को आधुनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित करना है। इसमें वैदिक गणित, योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, खगोलशास्त्र, साहित्य और नैतिक शिक्षा को शामिल करने की स्पष्ट दिशा दी गई है। नीति में यह मान्यता है कि शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज सुधार, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम भी है।

नीति के अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में संस्कृत और भारतीय भाषाओं का संवर्धन शामिल है। संस्कृत को केवल सांस्कृतिक संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि वैदिक ग्रंथों और भारतीय ज्ञान परंपरा तक पहुँच का माध्यम मानकर इसके अध्ययन को प्रोत्साहित किया गया है। इसी प्रकार, योग और ध्यान को विद्यालयी पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाकर छात्र के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा, NEP 2020 गुरु-शिष्य परंपरा का पुनरुत्थान करने की दिशा में भी कदम उठाती है। शिक्षकों को केवल ज्ञान प्रदान करने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शक और मेंटर के रूप में

स्थापित किया गया है, जिससे छात्रों का समग्र व्यक्तित्व विकसित हो और वे जीवन में नीतिपरक निर्णय लेने में सक्षम बनें।

संक्षेप में, NEP 2020 वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच सेतु का कार्य करती है। यह नीति परंपरा और नवाचार के संतुलन से शिक्षा को अधिक समग्र, नैतिक और प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्य आधारित शिक्षा का समन्वय स्थापित किया जाता है, जो उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा और जीवन के नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है।

NEP 2020 में वैदिक शिक्षा के तत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वैदिक शिक्षा की मूल अवधारणाओं और तत्वों को समकालीन शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का विशेष प्रयास किया गया है। नीति का दृष्टिकोण केवल प्राचीन ज्ञान का संरक्षण नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक शिक्षा के साथ संतुलित और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करना है। छम्ह 2020 में वैदिक शिक्षा के निम्नलिखित प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं—

1. भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश

नीति में स्पष्ट रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली को पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, योग, खगोलशास्त्र और वैदिक गणित जैसी विषयवस्तुओं को आधुनिक पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय ज्ञान के मूल तत्वों से परिचित कराना और उन्हें जीवनोपयोगी कौशल प्रदान करना है।

2. संस्कृत और भाषाई शिक्षा

संस्कृत भाषा को NEP 2020 में शिक्षा का अभिन्न हिस्सा मानकर उसके अध्ययन को सभी शैक्षिक स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया है। संस्कृत के माध्यम से छात्र वैदिक ग्रंथों, साहित्य और दर्शन तक सीधे पहुँच सकते

हैं। इसके अतिरिक्त, नीति में भारतीय भाषाओं के संवर्धन पर भी जोर दिया गया है, जिससे स्थानीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का संरक्षण सुनिश्चित हो।

3. नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा

वैदिक शिक्षा की तरह NEP 2020 में नैतिक मूल्यों, करुणा, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवतावाद को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को केवल विद्वान बनाना नहीं, बल्कि सद्गुण और नैतिकता के साथ समाज में योगदान देने वाले व्यक्तित्व के रूप में तैयार करना है।

4. योग, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य

नीति में योग और ध्यान को विद्यालयी पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाना शामिल है। यह विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने का माध्यम है। योग और ध्यान के अभ्यास से छात्रों में संतुलित मानसिक स्थिति, ध्यान और मानसिक सहनशीलता विकसित होती है, जो वैदिक शिक्षा का मूल उद्देश्य रहा है।

5. गुरु-शिष्य परंपरा का पुनरुत्थान

NEP 2020 में शिक्षकों की भूमिका केवल ज्ञान प्रदाता तक सीमित नहीं रह गई है। नीति उन्हें मार्गदर्शक, मेंटर और मार्गदर्शनकर्ता के रूप में स्थापित करती है। यह दृष्टिकोण वैदिक शिक्षा की गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप है, जिसमें गुरु छात्र के जीवन और चरित्र निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देता है।

इस प्रकार, NEP 2020 में वैदिक शिक्षा के तत्वों का समावेश न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का माध्यम है, बल्कि यह छात्रों के समग्र विकास, नैतिकता, कौशल और जीवनोपयोगी शिक्षा की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। नीति आधुनिक शिक्षा और प्राचीन ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित कर शिक्षा को अधिक प्रभावी, समग्र और सुसंगत बनाती है।

वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का समन्वय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैदिक शिक्षा को ज्यों-का-त्यों लागू करने के बजाय उसके मूल तत्वों को आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वित करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य छात्रों को न केवल प्राचीन ज्ञान से अवगत कराना है, बल्कि उन्हें आधुनिक दुनिया की आवश्यकताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना भी है। इस समन्वय में तीन प्रमुख दृष्टिकोणों पर विशेष बल दिया गया है।

1. परंपरा और नवाचार का संतुलन

नीति में परंपरागत ज्ञान और नवाचार के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है। वैदिक गणित, योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन जैसे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और नवाचार से जोड़ा गया है। इससे छात्रों को दोनों दुनियाओं का लाभ मिलता है। वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों और ज्ञान परंपरा से जुड़े रहते हैं, वहीं आधुनिक दुनिया की आवश्यकताओं के लिए सक्षम भी बनते हैं।

2. आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक दृष्टि का संयोजन

NEP 2020 आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन स्थापित करती है। योग, ध्यान और नैतिक शिक्षा छात्रों में आध्यात्मिक चेतना और आत्मबोध विकसित करती हैं, जबकि विज्ञान, तकनीक और तर्क आधारित शिक्षा उन्हें वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार, नीति छात्रों के समग्र विकास के लिए दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय करती है।

3. नैतिकता और कौशल विकास का एकीकरण

नीति केवल कौशल विकास या तकनीकी दक्षताओं तक सीमित नहीं है। यह नैतिक शिक्षा, करुणा, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों को व्यावहारिक कौशलों के साथ जोड़ती है। इस संतुलन से छात्र न

केवल पेशेवर रूप से सक्षम बनते हैं, बल्कि समाज में जिम्मेदार और नैतिक नागरिक के रूप में भी तैयार होते हैं।

संक्षेप में, NEP 2020 वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच एक संतुलित सेतु का कार्य करती है। यह नीति छात्रों को ज्ञान, मूल्य, कौशल और आध्यात्मिक चेतना के समन्वित विकास की दिशा में अग्रसर करती है, जिससे वे समग्र रूप से सशक्त, नैतिक और जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वैदिक शिक्षा और समग्र विकास के समन्वय पर विशेष बल दिया है। नीति में योग, ध्यान, संस्कृत, भारतीय ज्ञान प्रणाली और नैतिक शिक्षा को आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। फिर भी इसे प्रभावी रूप से लागू करने में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं।

1. वैदिक ग्रंथों की समकालीन व्याख्या

वैदिक ग्रंथ प्राचीन भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों में लिखे गए हैं। आधुनिक छात्रों के लिए इनका अर्थपूर्ण और व्यावहारिक रूपांतरण आवश्यक है। यदि इन्हें सरल और वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया, तो छात्रों को उनके महत्व और उपयोगिता का सही ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए शिक्षक और पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए यह चुनौती है कि वे वैदिक ग्रंथों की शिक्षण पद्धति को आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण और जीवनोपयोगी संदर्भ के अनुसार अनुकूलित करें।

2. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी

NEP 2020 में गुरु-शिष्य परंपरा और मार्गदर्शन केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या और प्रशिक्षण में अंतर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधक बनता है। प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक ही छात्रों में

समग्र विकास, योग, ध्यान और नैतिक मूल्य स्थापित कर सकते हैं।

3. पाठ्यक्रम और समय का संतुलन

आधुनिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और वैदिक शिक्षा के तत्वों को संतुलित रूप से पाठ्यक्रम में शामिल करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए सुविचारित पाठ्यक्रम संरचना, शिक्षण रणनीतियाँ और समय प्रबंधन की आवश्यकता है। यदि संतुलन नहीं बना, तो छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है या वैदिक शिक्षा के मूल उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाएंगे।

4. शहरी और ग्रामीण शिक्षा में अंतर

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संसाधन, शिक्षक उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैदिक शिक्षा, योग और संस्कृत जैसी गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू करना कठिन हो सकता है। इस असमानता को दूर करने के लिए सरकारी और निजी प्रयासों से समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

5. सांस्कृतिक और मानसिक स्वीकार्यता

आधुनिक छात्र और शिक्षक कभी-कभी पारंपरिक ज्ञान और वैदिक शिक्षा के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, मूल्य संवर्धन और व्यावहारिक शिक्षा मॉड्यूल तैयार करना आवश्यक है, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों वैदिक शिक्षा के महत्व और प्रासंगिकता को स्वीकार करें।

इन चुनौतियों को दूर किए बिना NEP 2020 के वैदिक शिक्षा समन्वय की पूरी सफलता संभव नहीं है। इसलिए नीति का प्रभावी क्रियान्वयन संपूर्ण योजना, प्रशिक्षित शिक्षक, संसाधन उपलब्धता और जागरूकता कार्यक्रमों पर निर्भर करता है।

सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के समन्वय को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं।

1. वैदिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना

प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में वैदिक शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। ऐसे केंद्र छात्रों को परंपरागत ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का अवसर प्रदान करेंगे। ये केंद्र न केवल वैदिक ग्रंथों और योग-ध्यान के अध्ययन का माध्यम होंगे, बल्कि जीवनोपयोगी कौशल, नैतिक मूल्यों और सामाजिक चेतना का विकास भी करेंगे।

2. शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार

नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग, ध्यान, नैतिक शिक्षा, संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक ही छात्रों के समग्र विकास और वैदिक शिक्षा के तत्वों को प्रभावी रूप से पाठ्यक्रम में लागू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षक छात्रों के मार्गदर्शक और मेंटर के रूप में कार्य करके गुरु-शिष्य परंपरा का भी निर्वाह कर सकते हैं।

3. डिजिटल और आधुनिक संसाधनों का विकास

संस्कृत, वैदिक गणित, योग, ध्यान और भारतीय दर्शन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक शिक्षण संसाधन तैयार किए जाने चाहिए। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑडियो-वीडियो लेक्चर और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से छात्रों को वैदिक शिक्षा आधुनिक संदर्भ में सुलभ और आकर्षक तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती है।

4. संतुलित पाठ्यक्रम निर्माण

आधुनिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और वैदिक शिक्षा के तत्वों का समन्वित पाठ्यक्रम तैयार करना आवश्यक है। यह संतुलन छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना उन्हें दोनों दृष्टिकोणों से ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी के तत्व भी शामिल किए जाने चाहिए।

5. जागरूकता और मूल्य संवर्धन कार्यक्रम

छात्रों और शिक्षकों में वैदिक शिक्षा के महत्व, योग और ध्यान के लाभ तथा नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष मूल्य संवर्धन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यह पहल छात्रों में नैतिकता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी के विकास में सहायक होगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैदिक शिक्षा के मूल आदर्शों नैतिकता, आध्यात्मिकता, समग्र विकास और गुरु-शिष्य परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पुनर्स्थापित करने का एक सशक्त और दूरगामी प्रयास है। नीति का दृष्टिकोण शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रखते हुए, छात्रों में समग्र व्यक्तित्व, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवनोपयोगी कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। छम्ह 2020 परंपरा और नवाचार, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक दृष्टि, तथा नैतिकता और कौशल विकास के बीच संतुलन स्थापित करती है। इस संतुलन के माध्यम से छात्रों को आधुनिक शिक्षा के वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया जाता है, जबकि वे अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़े रहते हैं।

नीति के माध्यम से छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्य आधारित शिक्षा का समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। यह न केवल उन्हें पेशेवर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि उन्हें सद्गुण, नैतिकता और सामाजिक चेतना के साथ

जीवन में निर्णय लेने में सक्षम भी बनाती है। यदि नीति को लागू करने में सामने आने वाली चुनौतियों को जैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम का संतुलन, संसाधनों की उपलब्धता और जागरूकता का समाधान प्रभावी ढंग से किया जाए, तो NEP 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम होगी।

संक्षेप में, NEP 2020 शिक्षा के क्षेत्र में परंपरा और आधुनिकता का संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह नीति छात्रों को समग्र, नैतिक, सशक्त और जीवनोपयोगी व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का यह समन्वय न केवल भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर को संरक्षित करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई दिल्ली—भारत सरकार।
- 2- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (2005), राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005, नई दिल्ली— NCERT.
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), (2023), विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा. नई दिल्ली।
4. यशपाल समिति, (1993), बिना बोझ के अधिगम नई दिल्ली— भारत सरकार।
5. राव, वी. एवं शर्मा, आर. (2018), वैदिक शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता. नई दिल्ली—अकादमिक प्रेस।
6. कुमार, पी. (2021), आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली का समावेश—एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और विकास पत्रिका, 12(3), 45–58।
7. सरस्वती, बी. एवं मिश्रा, ए. (2017), गुरुकुल परंपरा, प्राचीन भारत में दर्शन और अभ्यास, दिल्ली— हेरिटेज पब्लिकेशन्स।
8. पतंजलि, (2002), पतंजलि योगसूत्र (अनुवाद, स्वामी प्रभववानंद और क्रिस्टोफर इशर्वुड), वेदान्ता प्रेस।
9. विवेकानंद, एस. (1907), राज योग. अद्वैता आश्रम।
10. अरविंद, एस. (1956), शिक्षा की नींव (The Foundations of Education), शांति आश्रम प्रकाशन।
11. शर्मा, आर. (2011), योग का छात्रों की शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रभाव. नई दिल्ली—शिक्षा अनुसंधान प्रेस।

**Creation of Globally Competent Teachers in the Light of National Education
Policy (NEP) 2020: An Indian Perspective**

Dr. Mukesh Kumar¹

Dr. Neeta Singh²

1. Lecturer College of Teacher Education(CTE) Gaya, Bihar

2. Assistant Professor, Department of Education A.N. College, Patna

Abstract

Educators are anticipated to prepare students to address complex global, cultural, technological, and ethical challenges in an increasingly interconnected world. India's National Education Policy (NEP) 2020 emphasises internationalisation, interdisciplinary learning, and the development of global competence within teacher education. Nonetheless, it remains unclear how these concepts are comprehended, implemented, and integrated into existing teacher education frameworks. Furthermore, there is a lack of comprehensive study about the contradictions between global educational frameworks and India's socio-cultural, institutional, and resource contexts. This study critically examines the concept of internationally competent teachers within the framework of NEP 2020 by analysing the policy's vision, foundational assumptions, and proposed revisions. It outlines conceptual shortcomings, practical challenges, and structural constraints that may hinder the achievement of internationally competent teacher preparation. The research utilises a conceptual and analytical approach rooted in policy analysis and a review of secondary literature. It asserts that while NEP 2020 provides a progressive framework, its effectiveness depends on local adaptability, institutional capability, and the availability of professional support networks. The report finishes by proposing solutions to address the divergence between policy objectives and classroom practise in cultivating teachers who are internationally competent while being culturally aware. **Keywords: NEP 2020, Teacher Education, Global Competence, Internationalization, Indian Knowledge System**

Introduction

interconnected environments. The Global Teaching Model and the Asia Society–OECD framework exemplify approaches that emphasise the significance of varied viewpoints, communicate information, skills, and attitudes such as effectively across cultures, and conduct critical thinking, intercultural empathy, responsible behaviours within and ethical global engagement for

educators aspiring to attain global competence. India's socio-cultural and institutional pluralism further complicates standardized approaches to global competence. Regional disparities in language, economic development, and institutional capacity mean that a uniform model of globally competent teaching may be neither feasible nor contextually appropriate (Kumar et al., 2025).

In teacher education, global competence is regarded as developmental, advancing along continua of knowledge, skills, and dispositions rather than being a static characteristic. Research underscores methodologies including the incorporation of cross-cultural content, experiential and collaborative initiatives, and deliberate contemplation of power dynamics, equity, and global interdependence to foster these competencies. NEP 2020 puts teachers at the heart of changes to education and suggests a complete overhaul of how teachers are trained. Some of the most important changes are that by 2030, the 4-year integrated B.Ed. will be the minimum qualification, there will be multidisciplinary universities and teacher education institutions, stronger practicum components, and National Professional Standards for Teachers. NEP 2020 puts teachers at the centre of changes in education and suggests a

complete overhaul of how teachers are trained. Some of the most important changes are that by 2030, the minimum qualification for teachers will be a four-year integrated B.Ed., universities and teacher education institutions will be more multidisciplinary, practicum components will be stronger, and there will be National Professional Standards for Teachers. The policy also stipulates that educators should receive continuous professional development, mentorship, and support from their schools to enhance the attractiveness and professionalism of the teaching career.

At the same time, it stresses the importance of Indian Knowledge Systems, multilingualism, constitutional values, and respecting India's cultural diversity in education. Several parts of NEP 2020 indirectly encourage the training of teachers who can work with people from all over the world. These include a focus on critical and creative thinking, inquiry-based and experiential teaching methods, digital and online learning, and learning about best practices and working with other academics from around the world. The policy's emphasis on multicultural and inclusive education—via mother-tongue instruction, awareness of marginalised groups, and appreciation of cultural pluralism—corresponds with global and

intercultural competence standards. Nonetheless, NEP 2020 fails to provide a clear definition of "global competence" for educators or to align this concept with specific standards, curriculum components, or assessment instruments in teacher education programs. In India, teacher education still has problems with uneven quality, lack of infrastructure, not enough teachers, and teaching methods that are focused on tests and lectures, especially in rural and private colleges. It is especially hard to put in place training that is globally focused, inquiry-based, and supported by technology in schools where there is little internet access, a lot of students per teacher, and a lot of old-fashioned ways of doing things. Parmigiani et al. (2022), states Multiple conceptual gaps become apparent while examining NEP 2020 in relation to the global competence literature. The policy integrates concepts of global citizenship, 21st-century skills, Indian civilizational values, and digital literacy, although it does not explicitly clarify how these elements collectively define a "globally competent" Indian educator.

Scholars of multicultural and pluralistic education argue that policies must go beyond superficial symbolic gestures towards diversity and directly address structural disparities, instructor

biases, and local power relations. The objectives of NEP 2020 for teachers to achieve global competence could remain only aspirational if sufficient funding, context-sensitive curriculum creation, and robust professional development aligned with well-defined global competence rubrics are not ensured. In argument to the alignment the paper contextualizes a globally competent teacher against two frameworks aswell (Global Teaching Model (GTM) and the Asia Society–OECD framework), tries to bring forth the contribution of NCERT in its effort to embed global competency through its multicultural programme that is one component of teacher training.

The paper demonstrates that global competence is not a singular or neutral construct, but rather a multidimensional and context-sensitive concept. It encompasses critical awareness, intercultural sensitivity, ethical responsibility, and action-oriented pedagogy.

Concept of Globally Competent Teachers

The concept of Globally Competent Teachers has acquired more significance as globalisation progresses, technological advancements develop, and nations become more interconnected. India's educational initiatives, particularly the National Education Policy (NEP) 2020,

regard teachers as more than mere conveyors of knowledge. They consider them as experts who assist students in their preparedness to succeed in a society that is global, multicultural, and knowledge-based.

Globally competent instructors are critical to achieving this goal.

A globally competent teacher possesses a thorough understanding of their subject matter, as well as awareness of global concerns, cultural diversity, and a wide range of perspectives from around the world. NEP 2020 underscores the need of equipping students with 21st-century abilities, including critical thinking, creativity, cooperation, communication, and ethical reasoning. Educators should include these abilities into the classroom to facilitate students' development into informed, responsible, and engaged global citizens. This aligns with India's commitment to fulfilling Sustainable Development Goal 4 (SDG-4), which seeks to ensure equal access to high-quality education and lifelong learning for all. From a policy perspective, globally competent educators possess awareness of and sensitivity to a diverse range of languages and cultures. NEP 2020 aggressively encourages multilingualism, instruction in students' native languages, and the preservation of cultural diversity. This approach allows

educators to comprehend the varied backgrounds of their students and to relate local knowledge frameworks to global ones. In this approach, students can acquire knowledge about the world while keeping faithful to Indian beliefs.

Global competence is characterised by an equilibrium between possessing a global outlook and maintaining strong ties to the local society. Another crucial aspect is professional competence and continual professional development (CPD). NEP 2020 states that teachers must be lifelong learners who are constantly learning new things about their subjects and how to teach them. Teachers can learn about best practises and innovative ideas in education from across the world by being digitally literate, utilising educational technology, and participating in national platforms such as DIKSHA and NISHTHA. This kind of experience enables them to develop learning environments that are learner-centered, inquiry-based, and experiential, as well as meeting global standards. Being globally competent as an educator also entails a sense of moral, social, and emotional responsibility. Laws stipulate that educators should instil in their students principles such as compassion for others, respect for human rights, responsible citizenship within a democracy, and the cultivation of

empathy. Engage pupils with pressing global concerns such as climate change, sustainability, public health, and social justice. This instils in them a sense of responsibility toward the world and its inhabitants. Teachers are also central to NEP 2020 since it recognises them as the most vital element in enhancing the quality of learning. Educators with global competence serve as leaders, role models, and collaborators, fostering classroom environments that are inviting and conducive to open dialogue, critical thinking, and the generation of innovative ideas. They do not solely provide education within schools; they also engage with communities and collaborate with international knowledge networks as part of their responsibilities.

Policies like NEP 2020 want to make sure that students can not only do well in school but also make a difference in a world that is becoming more globalised and connected. People who are teachers are said to be globally competent if they know how to work well in classrooms with students from different cultures, use technology, and are linked to the rest of the world. The teachers in this group teach their students about other cultures, make them think critically about global issues, and prepare them to be responsible citizens of the world.

These competencies include specialised knowledge in one's discipline, innovative teaching methodologies, proficiency in the application of technology, an awareness of ethical considerations and effective communication with individuals from diverse cultural backgrounds, adaptability, and the capacity for critical self-reflection on one's practises. It is crucial to acknowledge that global competence does not entail standardising all cultures. Instead, it involves the ability to connect local conditions to global realities in a substantive and accountable manner.

NEP 2020 anticipates the process of internationalisation taking place through academic partnerships, exchange programmes, and compliance with global standards. At the same time, it highlights Indian knowledge systems, cultural heritage, and value-oriented education. This dual emphasis creates both opportunities and challenges. Integration possesses the capacity to improve teacher education; nevertheless, it necessitates careful planning to guarantee that both global and indigenous elements are really integrated rather than just included for superficial look. Teacher educators must be prepared to navigate this balance with deliberate thinking and scholarly precision.

Comparison of the Global Models

The Global Teaching Model (GTM) and the Asia Society–OECD framework both advance global competence in education but differ in structure, emphasis, and application to teacher practices. GTM organizes globally competent teaching into four interconnected factors: situated (culturally relevant to local contexts), integrated (woven into existing curricula), critical (addressing power, equity, and biases), and transactional (fostering intercultural collaboration).

The Asia Society–OECD model, by contrast, defines four student capacities: investigate the world, recognize perspectives, communicate across cultures, and take action for sustainable development. These approaches overlap in promoting inquiry, empathy, and action, yet GTM targets teacher pedagogy directly while Asia Society–OECD focuses on student outcomes that teachers enable.

Table 1.1: The Aspects against the Framework

Aspect	Global Teaching Model (GTM)	Asia Society–OECD Framework
Primary Focus	Teacher practises and classroom application	Student capacities and assessment.
Key Dimensions	Located, interconnected, analytical, transactional	Investigate world, recognize perspectives, communicate ideas, take action
Theoretical Lens	Postcolonial Theory and Critical Equity	Global citizenship, SDGs, broad international applicability
Strengths	Practical guidelines for the local integration and decolonization of curricula	Policy-aligned, scalable for systems-wide adoption
Challenges Addressed	Stereotypes, power imbalances, non-travel internationalization	Active learning amid rapid global changes

Explore the different components of multicultural exposure in existing

B.Ed. Program of RIE, Bhubaneswar in the Creation of Globally Competent Teachers in the Light of National Education Policy (NEP) 2020

The Regional Institute of Education (RIE) program aligns variably with the Global Teaching Model (GTM) and Asia Society–OECD framework by embedding diversity exposure, equitable practices, and reflective pedagogies, though gaps exist in explicit global issue integration and assessment rigor.

The components of the multi-exposure program have been analyzed and the variables of global competency are plotted against each of the components to realize whether the program itself fulfills the NEP 2020, values of a globally competent teacher.

Table 1.2: Multicultural Exposure Program Elements and Contribution to Global Elements

Program Element	Contribution to Global Competence
Diverse staff efforts	Builds intercultural empathy in local-global contexts
Exposure to three school types	Fosters adaptability to pluralistic settings
Observing regular teachers/peers	Enhances critical reflection on practices
Tips from regular	Practical

Program Element	Contribution to Global Competence
teachers	intercultural teaching strategies
Support for non-English proficient students	Promotes inclusive global citizenship
Teaching stereotyping effects	Shapes anti-bias global awareness
Pedagogy/diversity practice opportunities	Core developmental pathway for competence
Diverse instructional materials	Enables perspective recognition
Varied assessment devices	Ensures evidence-based improvement
Equitable IT/learning resources	Bridges digital divides globally
Equal status in activities	Reinforces inclusive global engagement
Gender-neutral teaching	Advances equity in global competence
Sharing anti-stereotype stories	Inspires responsible global citizenship
School environment observation	Contextualizes global issues locally
Case study support	Deepens intercultural inquiry skills
Lesson notes/plan training/samples	Structures globally competent delivery

Adopting an entirely new syllabus presents considerable hurdles for educators, requiring intensive pre-class preparation that places a substantial

demand on time and resources. Exacerbating this issue are inadequate teacher training programmes and a scarcity of qualified trainers, often necessitating additional hours beyond standard responsibilities. The lack of well-defined curricula and appropriate teaching tools further diminishes the quality of training, while limited technological expertise results in dependence on questionable internet content. Educators also face challenges

in maintaining work-life balance due to the demands of developing course materials, engaging students, and adjusting to emerging technologies, which are often time-consuming and stressful. Integrating skill development through social and co-curricular activities introduces additional complexity, as does obtaining school infrastructure, management support, parental approval, and implementing new evaluation methodologies.

Table 1.3 Total effectiveness of Multi-Cultural Programme in Global Competency Development in Teachers

Criterion	Rating (High/Med/Low)	Rationale
Situated/Critical Pedagogy	High	Robust anti-bias and diversity embedding counters stereotypes effectively.
Transactional Practice	High	Multi-school exposure builds adaptability.
Assessment Rigor	Medium	Varied devices exist but lack global competenc
Global Issue Integration	Low	Implicit local focus over explicit transnational inquiry.
Scalability in India	Medium	Strong on equity, challenged by infrastructure variances.

The case-based examination of the B.Ed. program at the Regional Institute of Education (RIE), Bhubaneswar, exemplifies this dynamic distinctly. The program shows a strong connection to the situated, critical, and transactional parts of

global competence, especially through multicultural exposure, anti-bias teaching, and diverse classroom practices. However, it doesn't do as well with explicit global issue engagement, transnational perspectives, and assessments that are specific to global competence. This suggests that Indian teacher education institutions may be implicitly promoting significant aspects of global competence; however, in the absence of a unified conceptual framework, curricular transparency, or stringent evaluation standards, these initiatives are inconsistent and challenging to expand.

This analysis indicates that the efficacy of NEP 2020 in cultivating globally competent educators relies not solely on the ambition of its vision, but also on the establishment of contextually relevant operational frameworks, clear competency standards, cohesive curricular integration, and strong professional support systems. Global competence should not be perceived as an external model or a mere policy aspiration; rather, it must be regarded as a locally implemented, critically informed, and ethically founded professional capability. Internationalizing teacher preparation can help teachers personally develop global competence and gain the knowledge and resources necessary for teaching global competence to their K-12 students

(Longview Foundation, 2008; Zhao, 2010). To be globally competent, students need global citizenship dispositions and the multiple literacies necessary for participation in a digital, global world (Kerkhoff, 2017). In order for change to occur in education, however, the extant literature shows that teachers must be trained in teaching global competence (Kerkhoff, Dimitrieska, Woerner, & Alsup, 2019; West, 2012; Yemini, Tibbitts, & Goren, 2019). The results also show that the problems with making teachers who are globally competent are not just about teaching methods, but also about the way the system is set up UNESCO. (2015). Infrastructural disparities, digital divides, uneven faculty capacity, and entrenched instructional traditions hinder the implementation of policy vision into practice, especially in under-resourced and rural settings. If there isn't ongoing funding, professional development, and institutional support, the goals of NEP 2020 may not become a reality.

Conclusion

The concept of global competency of teacher, in the Indian context as implied by NEP 2020 has been critically debated in the concerned study which make an argument that global competence is neither neutral in context nor a globally applicable construct. Instead it is ethically grounded professional competency that needs to be

carefully studied in the socio-cultural framework of India. NEP 2020 presents a visionary it does not detail conceptual framework, curriculum pathway and assessment structure for supporting and accessing the Indian teacher in the global competence structure.

This comparative study analyses global competency of teacher from the perspective of National Education Policy 2020 against the Global Teaching Model, and the Asia Society–OECD framework, demonstrating that policy discussions implicitly incorporate key aspects of global competence. These aspects include intercultural sensitivity, moral-ethical structure, inquiry-based learning, and plurilingualism at its base. This indicates that Indian teacher education institutions may already be cultivating key aspects of global competency; yet, without a cohesive conceptual and curricular framework, these initiatives remain challenging to expand, assess, or maintain. The case-based examination of the B.Ed. programme at the Regional Institute of Education (RIE), Bhubaneswar, exemplifies this dynamic distinctly. The programme exhibits a robust alignment with the contextual, critical, and transactional aspects of global competency through intercultural exposure, anti-bias pedagogies, and interaction with varied educational environments. Nevertheless, the restricted

inclusion of explicit global concerns, international viewpoints, and specialised evaluation methods indicates a partial and implicit strategy rather than a comprehensive and systematic approach.

In context to the above, global competence should not be treated as a supplementary component that is an addition to the main framework of teacher education. Rather, it should be considered as a locally embedded, critically engaged and ethically situated professionally: one which combines global awareness with social commitment; and situates international perspectives in local contexts. Internationalization of teacher education in India thus requires policy reformist changes, epistemological formulation, curricular integration, institutional capacity building and continuance engagement between international educational dialogue and the complex social-cultural contexts dominant in India.

There is also some indication that the problems associated with preparing globally capable teachers are as much, if not more, structural than they are pedagogical in nature. Inequities in infrastructure, digital divides, the consistency of staff preparedness, as well as entrenched instructional practices prevent policy vision from being translated effectively into classroom practice – particularly in rural and disadvantaged

environments. As a result, the effectiveness of NEP 2020 hinges on not just the thoroughness and salience of its normative formulations but also the evolution of suitable operational frameworks that are responsive to context, consistent investment in institutional capacity, and creation of robust cultures of professional support.

In conclusion, NEP 2020 offers a significant normative and structural basis for rethinking teacher education in India; however, its potential can only be fulfilled through meticulous conceptual elucidation, institutional capacity enhancement, and ongoing empirical engagement with classroom realities. To make teachers in India more globally competent, we need to change not only the rules but also the way they teach, give them more power, and keep the conversation going between global educational discourses and local socio-cultural contexts.

References

Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education, New Delhi.

Kumar, A., Hota, S. L., Kumar, A., & Khan, S. (2025). Indian primary schools and pluralism education – a qualitative view. *International Journal of Pluralism and Economics Education*, 15(4), 345–361.

<https://doi.org/10.1504/ijpee.2025.15355>

Longview Foundation . 2008. Teacher preparation for the global age: The imperative for change. <https://longviewfdn.org/programs/internationalizingteacherprep/> Retrieved on 3rd Nov'2025 from.

Kerkhoff S.N. (2017). Designing global futures: A mixed methods study to develop and validate the teaching for global readiness scale. *Teaching and Teacher Education* 91–106.

Kerkhoff S.N., Dimitrieska V., Woerner J., Alsup J. (2019) Global teaching in Indiana: A quantitative case study of K-12 public school teachers. *Journal of Comparative Studies and International Education*;1(1):5–31

National Council for Teacher Education (2021). *Teacher Education Curriculum Framework*. New Delhi: NCTE.

Parmigiani, D., Jones, S., Silvaggio, C., Nicchia, E., Ambrosini, A., Pario, M., Pedevilla, A., & Sardi, I. (2022). Assessing global competence within teacher education programs. How to design and create a set of rubrics with a modified Delphi method. *SAGE Open*,12(4).

<https://doi.org/10.1177/21582440221128794>

UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Preparing Learners for the*

Challenges of the 21st Century. Paris: UNESCO.

West C. NAFSA; 2012. Toward globally competent pedagogy [PDF] http://www.nafsa.org/uploadedFiles/Ch ez_NAFSA/Find_Resources/Publications/Periodicals/Epublications/epub_toward_globally.pdf

Yemini M., Tibbitts F., Goren H. Trends and caveats: Review of literature on global citizenship education in teacher training. Teaching and Teacher Education. 2019;77(1):77–89.

Zhao Y. Preparing globally competent teachers: A new imperative for teacher education. Journal of Teacher Education. 2010;61(5):422–43.

INTEGRATION OF TECHNOLOGY IN EDUCATION UNDER (NATIONAL
EDUCATION POLICY) NEP 2020

Dr. Manik Mohan Shukla

HoD, Deptt. of Education, A.M. College, Gaya

Rani Neena Priyadarshini

**Research Scholar, Magadh University,
Bodhgaya**

ABSTRACT

The integration of technology in education is a cornerstone of the National Education Policy (NEP) 2020, aimed at transforming India's education system to meet the demands of the 21st century. NEP 2020 envisions leveraging technology to enhance learning outcomes, improve accessibility, and foster inclusivity, ensuring that all students, regardless of their background or location, have access to quality education. The policy emphasizes the development of digital infrastructure, the promotion of digital literacy, and the use of innovative learning models such as blended learning. It also highlights the importance of teacher training in digital pedagogy to support effective technology integration in classrooms. Through platforms like DIKSHA and SWAYAM, NEP 2020 seeks to create a flexible, personalized learning environment, where students can access resources tailored to their needs. Despite challenges like the digital divide and the need for comprehensive teacher training, NEP 2020 offers a transformative vision for India's educational future, where technology plays a pivotal role in shaping an equitable and high-quality education system.

Keywords: Rapid, Technology, Mind, Education, Policy.

1. INTRODUCTION

The rapid advancements in technology over the past few decades have dramatically transformed various sectors, with education being one of the most affected areas. As the world becomes increasingly interconnected through the internet and digital platforms, the need for integrating technology into the educational ecosystem has never been more urgent. In India, where education plays a critical role in shaping the future of millions of young minds, the government has recognized the importance of leveraging technology to enhance educational outcomes. The National Education Policy (NEP) 2020, introduced by the Government of India, is a significant step toward revamping the country's educational landscape. One of the key pillars of this policy is the integration of technology into education, aiming to bridge gaps in access, improve

quality, and make learning more personalized and inclusive. NEP 2020 envisions the use of technology to create a robust, adaptable, and globally competitive education system, one that is prepared for the challenges of the 21st century. The NEP 2020 places technology at the heart of its reform agenda, seeing it not merely as a tool but as an essential enabler of educational transformation. The policy recognizes that the digital divide remains a major challenge, particularly in rural and underserved regions, and thus, a critical focus is placed on expanding access to technology. This is achieved by recommending the development of digital infrastructure, ensuring equitable access to devices and internet connectivity, and creating scalable, inclusive, and flexible learning models. The goal is to ensure that every student, regardless of their background or location, has the opportunity to benefit from high-quality digital education.

In its vision for technology in education, NEP 2020 aims to achieve several broad objectives: enhance teaching and learning processes, promote digital literacy, improve educational access and equity, and create an environment where students can thrive in an increasingly digital world. The policy highlights the need for digital content, resources, and platforms that cater to diverse learning

needs and are aligned with national standards. For instance, it emphasizes the use of platforms like DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing), SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds), and other digital learning resources to supplement classroom learning, ensuring that education is not limited to traditional methods or physical spaces. NEP 2020 also pushes for the use of Artificial Intelligence (AI), data analytics, and other cutting-edge technologies to personalize learning, monitor student progress, and provide real-time feedback to students and educators. Moreover, NEP 2020 places a significant emphasis on teacher professional development, recognizing that teachers are central to any educational transformation. The policy proposes a shift toward developing educators who are not only digitally literate but also skilled in using technology to enhance their teaching methods. By integrating technology into teacher training, the policy aims to ensure that educators are equipped with the tools they need to navigate the digital classroom and provide effective instruction that fosters critical thinking, creativity, and problem-solving skills. In this context, digital pedagogy becomes an integral part of teacher education and professional development.

One of the most notable aspects of learning platforms can transcend NEP 2020's vision is its focus on blending geographical barriers, allowing students in technology with traditional classroom far-flung regions to access high-quality teaching to create a dynamic, flexible educational content that was previously learning environment. This blended unavailable to them. Furthermore, digital learning model, which combines online education has the potential to support education with face-to-face interaction, is students with disabilities by providing designed to cater to different learning specialized tools such as screen readers, styles and paces, thus fostering a more sign language interpreters, and subtitles, personalized learning experience. The ensuring that they can participate in flexibility inherent in blended learning mainstream education alongside their allows students to engage with educational peers. NEP 2020 also advocates for the content outside of the traditional creation of high-quality digital educational classroom, providing them with content that is available in multiple opportunities to learn at their own pace, languages, making it accessible to students revisit complex concepts, and access a from diverse linguistic backgrounds. The wider array of resources. In this model, the policy acknowledges the rich cultural role of the teacher shifts from being the diversity of India and proposes the sole source of knowledge to being a development of educational resources that reflect this diversity, ensuring that students can learn in their native languages and engage with content that is culturally Technology thus becomes a crucial support relevant. This multilingual approach to system for both teachers and students, enhancing the overall educational digital education not only enhances experience. In terms of inclusivity, NEP accessibility but also fosters inclusivity, 2020 envisions using technology to ensuring that no student is left behind due to language barriers.

2. TECHNOLOGY IN EDUCATION:
A VISION OF NEP 2020

NEP 2020 outlines a clear vision for the integration of technology across various levels of education. It recognizes that technology can foster personalized learning, enable better access to resources,

and support teachers in their professional growth. The policy underlines the importance of a robust digital infrastructure, equitable access to technology, and the alignment of technological tools with educational outcomes. Key areas where technology is integrated into education under NEP 2020 include:

1. Digital Learning Platforms:

- NEP 2020 emphasizes the need for expanding the scope of digital learning by promoting online platforms, content creation, and virtual classrooms.
- It encourages the use of platforms such as the National Repository of Open Educational Resources (NROER), DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing), and e-Pathshala to provide access to quality content and learning materials.

2. Blended Learning Models:

- The policy advocates for the adoption of blended learning models, combining traditional face-to-face teaching with digital resources.
- This approach helps in creating more flexible learning environments and makes education more adaptable to individual needs.

3. Digital Pedagogy:

- NEP 2020 promotes the use of technology for enhancing pedagogical practices, such as interactive learning, data-driven assessment, and the use of artificial intelligence (AI) for personalized instruction.
- Digital tools can support active learning, critical thinking, and problem-solving skills, moving away from rote memorization.

4. Teacher Professional Development:

- The policy stresses the importance of teacher training in digital literacy and the use of educational technology.
- NEP 2020 encourages the development of continuous professional development (CPD) programs that help teachers integrate technology into their teaching practices.

5. Access to Education for All:

- NEP 2020 aims to use technology to overcome geographical, economic, and social barriers to education. It stresses the importance of providing educational access to underserved populations, especially in remote areas.
- Initiatives like SWAYAM (Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds) and PM

eVidya are aimed at creating accessible and affordable educational opportunities.

3. KEY STRATEGIES FOR IMPLEMENTATION

The successful integration of technology in education under NEP 2020 relies on the following strategies:

1. Building Robust Digital Infrastructure:

- A significant part of NEP 2020's vision is building reliable digital infrastructure. This includes increasing internet connectivity in rural and underserved areas, providing devices to students and teachers, and enhancing the capacity of digital platforms to handle increased traffic.

2. Promoting Digital Literacy:

- NEP 2020 acknowledges that digital literacy is essential for both students and teachers. It recommends integrating digital literacy as a core component of the curriculum from the early stages of education.
- By ensuring that students and educators are proficient in using digital tools, technology can be leveraged more effectively in the learning process.

3. Creating and Curating High-Quality Content:

- NEP 2020 calls for the creation of quality digital educational content in multiple languages. This content must align with the national curriculum framework, ensuring consistency and relevance.

- Platforms like DIKSHA aim to provide resources that are not only interactive but also culturally appropriate and in diverse languages.

4. Enhancing Teacher Training and Support:

- Professional development for teachers remains a priority. The policy calls for targeted training programs on how to use digital tools effectively, how to assess students through digital means, and how to create engaging and inclusive online learning experiences.

5. Promoting Inclusive Education through Technology:

- NEP 2020 stresses the role of technology in facilitating inclusive education. Technology can help in accommodating students with diverse learning needs, disabilities, and language barriers through tools like screen readers, captioning, and sign language interpreters.

6. Leveraging Artificial Intelligence (AI) and Data Analytics:

- The policy recognizes the potential of AI and data analytics in personalizing education. These technologies can help in identifying learning gaps, tracking student progress, and providing real-time feedback to students and teachers.

4. CHALLENGES IN INTEGRATING TECHNOLOGY IN EDUCATION

Despite the promising vision of NEP 2020, several challenges remain in the integration of technology in education:

1. Digital Divide:

- A significant challenge is the digital divide between urban and rural areas, which impacts access to technology. Many students in remote areas lack the infrastructure and devices needed to participate in digital education.

2. Teacher Resistance and Training Gaps:

- There is often resistance from teachers who are not familiar with digital tools and online teaching methods. Adequate training and support are essential to overcome this barrier.

3. Data Privacy and Security:

- With the increased use of digital platforms, concerns about data privacy and security arise. Protecting the personal information

of students and ensuring the safety of online platforms is crucial.

4. Infrastructure Limitations:

- Inadequate internet connectivity and a lack of necessary devices in many parts of the country remain significant obstacles to the successful implementation of NEP 2020.

5. Quality Control:

- Ensuring the quality of online content and resources is another challenge. There is a need for continuous monitoring to ensure that educational content meets the required standards.

6. POTENTIAL OUTCOMES OF TECHNOLOGY INTEGRATION UNDER NEP 2020

The successful integration of technology in education as envisioned by NEP 2020 could lead to several positive outcomes:

1. Enhanced Learning Experiences:

- Technology can offer personalized learning experiences, where students progress at their own pace, access resources tailored to their needs, and receive immediate feedback.

2. Improved Accessibility:

- Technology can provide equal learning opportunities for all, particularly for marginalized

communities, students in remote areas, and those with disabilities.

-
- 3. **Global Learning Opportunities:**
- NEP 2020 opens up the possibility of students participating in global learning networks, accessing a wealth of international resources, and collaborating with peers worldwide.
- 4. **Efficient Use of Resources:**
- The efficient use of digital platforms and tools can reduce the reliance on physical infrastructure, make learning materials available to all at minimal cost, and ensure scalability.
- 5. **Better Teacher Support:**
- Teachers will benefit from digital platforms that provide continuous professional development, access to a variety of teaching resources, and collaborative spaces for sharing best practices.

7. CONCLUSION

The integration of technology in education, as outlined in NEP 2020, holds great promise for transforming the Indian education system. By embracing digital tools, fostering blended learning, and addressing the challenges of accessibility and infrastructure, India can create a more inclusive, efficient, and progressive education framework. However, the

success of this integration will depend on the collective efforts of governments, educators, institutions, and the private sector to overcome the barriers to technology adoption and ensure that all students benefit from these advancements. The future of education in India, as envisioned by NEP 2020, will be shaped by the strategic and effective integration of technology, paving the way for a more equitable and innovative educational landscape.

REFERENCES

- Bell, C., & Rousseau, P. L. (2001). Post-independence India: A case of finance-led industrialization? *Journal of Development Economics*, 65(1), 153-175. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(01\)00157-0](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(01)00157-0)
- Bureau of Education. (1965). *Selections from educational records, Part I (1781-1839)* (H. Sharp, Ed.). National Archives of India. (Original work published 1920)
- Katrak, H. (1997). Developing countries' imports of technology, in-house technological capabilities, and efforts: An analysis of the Indian experience. *Journal of Development Economics*, 53(1), 67-83. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(97\)00029-0](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(97)00029-0)
- Saha, S. (2012). Productivity and openness in the Indian economy. *Journal of Applied Economics and Business Research*, 2(2), 91-102.

State, Law, and Lawlessness: Failure of the Governance in Train to Pakistan

Aditi Rai

P.G. Student

Dr. Tulika Tripathi

(Assistant Professor)

St. Joseph's College for Women Civil Lines, Gorakhpur

ABSTRACT

This research paper scrutinizes the negligence of the government and failure of law in Khushwant Singh's Train to Pakistan. The novel is set during the Partition of India in 1947, the novel accentuates the collapse of government authority and how frail administration, political decisions, and sectarianism led to extensive violence and widespread lawlessness. The study focuses on the collapse of government authority, the misuse of police power, the impotence of the state to protect innocent citizens, the decline of humanity, and the irresponsibility of society during Partition of India. Jugga's sacrifice stands in contrast to failure of state law and his sacrifice is a symbol of moral law and human conscience. The paper also investigates how riots and violence supersede state control and how average citizens suffer due to political negligence. This research paper uses a thematic and textual analysis of the novel. Therefore Train to Pakistan is a strong criticism of failed law, negligence of government, irresponsible leadership and irresponsible act of society.

Introduction

Khushwant Singh was born as Khushal Singh in Hadali, Punjab Province, British India, which is now in Punjab, Pakistan. He had witnessed the Partition of India and its violence, slaughter, sectarian strife, rape and mass migration. His work Train to Pakistan mirrors every aspect of the Partition of India-one of the most violent episodes in South Asian history and through this novel Singh paints the authentic picture of horrors of Partition,

but in a very skilful manner he bestows upon us the ground realities and failure of governance which obliquely adds fuel to the fire of Partition. The character of Hukum Chand, who was the magistrate and deputy commissioner and his inability to save people and his powerlessness in preventing the massacre convey the failure of governance and this culminates in chaos and brutality. "Why had he let the girl go back to Chundunnugger? Hukum Chand slid off his chair, covered his face with his arms and started to cry. Then he

raised his face to the sky and began to pray” (Singh 188). The lines reveal Hukum Chand’s helplessness. The narrative shows that when the state fails to maintain law and order, ordinary people are left vulnerable to fear and violence. This paper contends that Train to Pakistan imparted the failure of governance during Partition, demonstrating how failure of state law stimulates lawlessness, moral disintegration and horrors of Partition.

Historical Context and the role of the State

India achieved its freedom at the stroke of midnight on August 15, 1947, while half of India was celebrating its freedom, the other half was facing the consequences of Partition. As Bhisham Sahni writes in his memoir, *Today’s Pasts: A Memoir*: “The Indian flag was flying instead of the Union Jack on government buildings, at police stations, and crossings, which made one feel that the nation really had become independent. At the same time, I also saw the crowd of refugees on the streets. On the one hand, there was a celebratory mood, but on the other was the misery of the homeless” (Bhisham Sahni).

India’s independence was marred by the tragic events of Partition. The abrupt withdrawal of British authority left freshly independent India and Pakistan inadequate to cope with the aftermath of

Partition. Bhisham Sahni’s memoir vividly reveals the failure of governance during the Partition and how abruptly the decision was made. Sahni recalls that the announcement that Pakistan was going to be created, the news came without any preparation and clarity, leaving ordinary citizens shocked and confused. He says, “this hurt me deeply. It was unexpected. There was no news of this” (Sahni’s *Today’s Pasts: A Memoir*). Sahni’s personal feelings stand as a powerful testimony to the collapse of government during Partition of India.

In the novel *Train to Pakistan*, Singh tries to demonstrate this vacuum of governance. The fictional village of Mano Majra, becomes a microcosm of India, in Mano Majra different religious communities lived in tranquility and uninfluenced by the Partition and its violence, “the only remaining oases of peace were a scatter of little villages lost in remote reaches of the frontier. One of these villages was Mano Majra” (Singh 02).

The tranquility of Mano Majra was shattered by the chaos of Partition, and this chaos was introduced by the administrative failure. Any state’s failure is initiated by its impotence to anticipate the consequences of hasty Partition and the state failure is also initiated when the state fails to provide adequate protection to

vulnerable communities. Through the novel Singh repeatedly encapsulates the impotence of state institutions; the police fail to put an end to violence or even minimize the aftermath of Partition, whereas the police focused more on the baseless situations. The police and political figures are either absent or ineffective when violence erupts. When Lambardara and few villagers saw the dead bodies coming through the arches of the bridge, one of them told to inform the police then the other man mockingly said, “Police? What will they do? Write a first information report?” (Singh 151). The lines represent the helplessness of villagers and failure of state authority.

Singh very efficiently uses his characters to display the failure of state, Hukum Chand’s absence from the vulnerable situation and the Subinspector’s plotting with the head constable to frame Iqbal and torture Juggut shows impotence of police and state failure. The subinspector’s statement, “there are many Iqbals. I am talking of a Mohammed Iqbal, you are thinking of Iqbal Singh. Mohammed Iqbal can be a member of the Muslim League” (Singh 113). This statement of subinspector shows his adamant behaviour which works not on evidence but on his impulse and bias, Juggut was jailed for no real crime and Iqbal was arrested because the state needs

a scapegoat. This shows the collapse of legal institutions and a failure of state.

The forced migration of Muslim community from Mano Majra reveals how the state was incapable and failed to protect its own citizens. Muslim community of Mano Majra evacuated their homes and packed their belongings to move to a new land they even left some of their belongings in the hope of returning back unaware of the fact that they won’t be able to see their neighbours again and they won’t be able to return to their real home. This was the reality of many commoners during the Partition. Through the people of Mano Majra Singh draws the picture of innocent people who had to face the brutal consequences of Partition because the government failed to uphold the society, people and nation together.

When Malli and his gang was plotting to attack on the train which was carrying Muslims to Pakistan and when Hukum Chand came to know about this conspiracy he said, “well, Inspector Sahib, let them kill.... Let everyone kill. Just ask for help from other stations and keep a record of messages you send. We must be able to prove that we did our best to stop them” (Singh 163). This declaration by Hukum Chand assert the ethical failure of the state.

Communalism and Lawlessness

Communalism one of the central themes of the novel, defined as an extreme allegiance to one's own religious group, triggers the collapse of social law and order. The British Government sowed the seeds of divide and rule and later sectarian strife was seen as one of the main drivers of Partition of India ultimately culminated in one of the most violent and brutal mass killings, mass displacement, arson, abductions, rape, and destruction of the entire nation. When governance and law enforcement are weak and people lose their faith in government, state and law's ability to protect them, then people revert to self-support mechanisms often culminate into violence against perceived "others".

Mano Majra lived peacefully, in initial time the shadows of Partition violence did not reach the village. However when "villagers discovered that the train had brought a full load of corpses" (Singh 124), and when villagers got the news of massacres elsewhere, it ignited the fear and hatred in villagers' minds. In this situation the first and foremost priority of any government and state would be to impose law and order and execute it peacefully with less to no casualties, nevertheless the state- that is the police and the magistrate thought of their

personal profit and turned communal at such a crucial moment.

The decisions of the state supported the chaos of Partition and added fuel to the fire of sectarian strife. Instead of enforcing law the state supported lawlessness. The sub-inspector's support to communalism, "that is the only way to stop killings on the other side. Man for man, woman for woman, child for child" (Singh 21), when he came to know that the Sikh community attacked the Muslim refuge train. His further statements such as "God alone knows what I would have done to these Pakistanis if I were not a government servant" (Singh 23) exhibits his communist ideologies and his hatred towards other religion.

Through the character of sub-inspector, Singh wants to convey the message of state failure during the crucial time of a nation and due to irresponsible behaviour of a state, lawlessness increases in a society and citizens of the society. When the police and magistrate take abrupt decision commoners had to survive and face the consequences. Failure of a state is a miniature form of failure of a governance. The decision of Partition was rushed and the government took this decision and never considered the ground level reality, the law was enforced but it was poorly implemented.

Reflection on Governance and Human Responsibility

The novel depicts the situation of ordinary humans and the moral dilemma they had to deal with when the government fails to protect them. The ordinary people's thoughts are like a pendulum, having too and fro motions between cruelty and compassion. The tranquil village of Mano Majra, where Hindus, Muslims, and Sikhs once lived in harmony and with love, their love for each other got shattered and the villagers started to pour hatred toward the Muslim community and the reason was "they are Muslims" (Singh 131). The dilemma of villagers between cruelty and compassion is apparent in the novel when villagers could not decide whether to give shelter to refugees or to ask their Muslim friends to leave the village, "the peasants thought about their problem. They could not refuse shelter to refugees: hospitality was not a pastime but a sacred duty when those who sought it were homeless. Could they ask their Muslims to go? Quite emphatically not" (Singh 132).

Khushwant Singh's *Train to Pakistan* is not only a political critic but also an ethical one. Singh through this novel asserts that governance is not only about policies, law, state, and institutions but also about the collective will of society to uphold justice and humanity at the

crucial moment of the nation. The government failed to accomplish this and the government appeared weak when the Muslim community was forcefully evacuated. The Muslims were sobbing and crying because they could not understand what they did wrong to leave their birth place; the place where their ancestors were born and lived, from the character of Imam Baksh Singh conveys the pain of many common people who had to leave their birth place because they belonged to a certain community which was acceptable either in India or in Pakistan.

Imam Baksh put forwards the pain of many common people by saying, "what have we to do with Pakistan? We were born here. So were our ancestors. We have lived amongst you as brothers" (Singh 133). The government could have stopped this forceful evacuation but government failed to do so and few people took charge into their hand and for the sake of humanity according to a few villagers, they started planning to kill Muslim community to take revenge for what has happened to the Sikh community in Pakistan. During Partition humans forgot humanity, morality, and human responsibility of being a human. The train from Pakistan carried innocent humans but in India only dead bodies reached and the following lines clearly give the picture of brutality

during Partition and collapse of law and humanity:

“They were murdered. An old peasant with a grey beard lay flat on the water. His arms were stretched out as if he had been crucified. His mouth was wide open and showed his toothless gums, his eyes were covered with film... A child’s head butted into old man’s armpit. There was a hole in its back...some were without limbs, some had their bellies torn open, many women breasts were slashed” (Singh 151).

Failure of governance is not only because of state, law, and lawlessness but also because of irresponsible act by the society. The hatred towards other community was baseless and few people brain was fogged with the thought of violence and the reason they had for their brutality that they are taking revenge for what happened with Sikhs and Hindus community on the other side of Radcliffe line. The moral decline and the irresponsible act of society was put forward by Singh in his novel and this also leads to the failure of governance. Singh paints the picture of 1947 society, which was easy to manipulate and lay out hatred. In the novel a teenager boy influenced the people of Mano Majra for violence and brutality through his inflammatory speech.

The people of Mano Majra got so much influenced by a boy in his teens that

they even forgot that they were also agreeing to kill those people who were like their own family. The inflammatory speech of boy included hatred, violence and revenge he said:

“for each Hindu or Sikh they kill, kill two Mussulmans. For each woman they abduct or rape, abduct two. For each home they loot, loot two. For each trainload of dead they send over, send two across. For each road convoy that is attacked, attack two” (Singh 157).

Through the novel Singh captured every aspect of government failure, with all other reasons of government failure during Partition of India, the ethical lapse of society, the corruption, the moral decline, the lawlessness and the transgression of society was also one of the major causes of failure of governance during Partition of India.

However the society did not lost all its touch from humanity, the character like Jugga was ray of hope for humanity during the darkness of Partition, he was a criminal by law but a moral hero by action. At the end of the novel Jugga sacrifices his life to save the Muslims travelling on the train, “the train went over him, and went on to Pakistan” (Singh 190). During the chaos of Partition where everyone was thirsty for each other’s blood, Jugga did not had a second thought and he sacrificed his life. On the other hand, character like Iqbal

represents the people who only boast but when there is time for action they fail to do so, according to Iqbal, “if there were people to see the act of self-immolation, as on cinema screen, the sacrifice might be worth while: a moral lesson might be conveyed” (Singh 179). Therefore the novel not only talks about the failure of government but also the failure of people to uphold human responsibility.

Fiction and Historical Reality

Though *Train to Pakistan* is a fictional story but it mirrors the real historical failures during Partition. Historical data confirms widespread administrative breakdown, delayed troop developments, and failure to control mass migration and violence. Many historians commented on the failure of governance during Partition of India even writers such as Urvashi Butalia in her seminal work *The Other Side of Silence*, argue ‘how the government and political leadership failed to anticipate and respond effectively to the monumental human cost and violence’ (Butalia). Hence Singh’s novel is not just a fictional portrayal, it reveals that the lack of clear legal authority and bureaucratic paralysis worsened the communal confrontation. The comparison between fictional story and documented history highlights a crucial point that literature can often revealed the emotional depth, the

moral truths and fatal consequences of a historical event that is often overlooked by official records.

Khushwant Singh’s *Train to Pakistan* poignantly demonstrates the collapse of state authority and legal order and failure of governance eventuate into lawlessness and chaos into society during one of India’s most turbulent periods in its history. The study reasserts that the novel *Train to Pakistan* presents the Partition of India as a period marked by administrative collapse, where state fails to protect its citizens and uphold justice. The paper analyzed how the absence and failure of governance give rise to violence, moral breakdown of society, riots and fear. Characters like Hukum Chand emblemize a corrupt and bewildered administration and on other hand Sub-inspector arresting Jugga symbolize the misuse of state power and the train carrying dead bodies symbolizes and villagers getting influenced to attack the train and to take revenge symbolizes the lawlessness of society and breakdown of law and order during Partition.

The direct relationship between failure of governance and human suffering, make the study significant. Singh’s keen observation of failure of governance during the Partition of India very efficiently depicted in his novel and the novel’s depiction of lawlessness goes

beyond a historical moment and offers a universal warning about the dangers of state failure and reminds that when government and state fail to act and implement the law effectively, the society falls into a chaos, injustice and violence.

This research is limited to textual and thematic analysis of the novel *Train to Pakistan*, it does not include the comparative study with other Partition novel or historical document. Future research may focus on exploring comparative study of Partition novels and representation of government, state authority and lawlessness during Partition of India within the novel. In conclusion, Khushwant Singh's *Train to Pakistan* vigorously illustrates that the failure of state and governance conclude not only the breakdown of law but also the loss of humanity. Through the realistic representation of Partition of India, the novel act as a continuing reminder that law, justice, responsibility and moral courage are indispensable for the survival of any civilized society.

Works Cited

1. Butalia, Urvashi. *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India*. Duke University Press, 2000.
2. Sahni, Bhisham. *Today's Pasts: A Memoir*. Translated by Nita Kumar, Penguin Books India, 2001.
3. Singh, Khushwant. *Train to Pakistan*. Penguin Books, 2007.
4. Talbot, Ian, and Gurharpal Singh. *The Partition of India*. Cambridge University Press, 2009.

शिक्षण शैलियों का माध्यमिक छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव: पटना जिले का एक शोध

मधु कुमारी

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

डॉ० गीता पाण्डेय

शोध निर्देशिका, शिक्षा विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

सार

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य पटना जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण शैलियों तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंध का अध्ययन करना है। ग्राशा (1996) द्वारा प्रतिपादित पाँच शिक्षण शैलियों विशेषज्ञ, औपचारिक प्राधिकारी, व्यक्तिगत आदर्श, सुविधादाता एवं प्रतिनिधायक को सैद्धांतिक आधार मानकर यह अध्ययन संपन्न हुआ। वर्णनात्मक सर्वेक्षण अभिकल्प पर आधारित इस शोध में पटना जिले के 12 माध्यमिक विद्यालयों से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा 400 छात्र तथा 80 शिक्षक चयनित किए गए। आँकड़ों के संकलन हेतु ग्राशा-रीचमान शिक्षण शैली सूची एवं विषयगत शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग हुआ। परिकल्पना यह थी कि शिक्षण शैली एवं उपलब्धि के बीच सार्थक संबंध विद्यमान है। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, 't'-परीक्षण, पियर्सन सहसंबंध तथा ANOVA का प्रयोग किया गया। परिणामों ने स्पष्ट किया कि सुविधादाता एवं व्यक्तिगत आदर्श शैलियों का उपलब्धि पर धनात्मक एवं सार्थक प्रभाव है, जबकि पूर्णतः विशेषज्ञ-केंद्रित शैली का प्रभाव अपेक्षाकृत न्यून रहा। निष्कर्षतः छात्र-केंद्रित शिक्षण शैलियों को अपनाने से पटना के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

मुख्य शब्द: शिक्षण शैली, शैक्षणिक उपलब्धि, माध्यमिक छात्र, पटना जिला, ग्राशा मॉडल

1. प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला है और इसकी गुणवत्ता का सीधा संबंध शिक्षक के कक्षा-व्यवहार एवं उसकी शिक्षण शैली से होता है। शिक्षण शैली वह स्थायी प्रतिमान है जिसके माध्यम से शिक्षक अपनी मान्यताओं, आवश्यकताओं एवं व्यवहारों को कक्षा में अभिव्यक्त करता है तथा विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करता है। ग्राशा (1994) ने पाँच प्रमुख शिक्षण शैलियाँ प्रतिपादित कीं विशेषज्ञ (सूचना का संवाहक), औपचारिक प्राधिकारी (मानक निर्धारक), व्यक्तिगत आदर्श (उदाहरण द्वारा शिक्षण), सुविधादाता (प्रश्नों एवं

विकल्पों द्वारा मार्गदर्शन) एवं प्रतिनिधायक (स्वायत्तता का विकास)। ये शैलियाँ शिक्षक की कक्षागत भूमिका को गहराई से प्रभावित करती हैं। बिहार राज्य, विशेषकर पटना जिला, भारत के उन क्षेत्रों में आता है जहाँ माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियाँ अत्यंत गंभीर हैं। पटना जिले की साक्षरता दर बिहार में सर्वाधिक लगभग 87.82 प्रतिशत है, किंतु इसके बावजूद माध्यमिक स्तर पर पठन-पाठन की गुणवत्ता एवं छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि में व्यापक विषमता देखी जाती है। राज्य में माध्यमिक स्तर पर विद्यालय त्याग की दर अत्यधिक है,

जिसका एक प्रमुख कारण अनुपयुक्त शिक्षण पद्धतियाँ भी मानी जाती हैं (पाण्डेय, 2023)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षाओं के आँकड़े बताते हैं कि विद्यार्थियों की उपलब्धि विषयवार एवं विद्यालय-प्रकार के अनुसार अत्यंत भिन्न है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या शिक्षकों द्वारा अपनाई गई शिक्षण शैली छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है? पारंपरिक रूप से पटना के अनेक विद्यालयों में व्याख्यान-प्रधान (विशेषज्ञ एवं औपचारिक प्राधिकारी) शैली प्रचलित है, परंतु आधुनिक शोध यह दर्शाते हैं कि छात्र-केंद्रित शैलियाँ अधिगम प्रतिफलों में वृद्धि करती हैं (नानावरे एवं बाविस्कर, 2023)। शर्मा (2019) ने भी यह मत प्रकट किया कि भारतीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण शैली और छात्र उपलब्धि के बीच सार्थक संबंध है। यह शोध इसी रिक्तता को भरने का प्रयास है। पटना जिले के सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण शैलियों का मानचित्रण करते हुए यह अध्ययन छात्रों की उपलब्धि पर इनके प्रभाव का अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह शोध पटना के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, बिहार बोर्ड की परीक्षा-प्रणाली तथा हिंदी-माध्यम के विद्यालयों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीति-निर्माताओं, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं प्राचार्यों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जिससे माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार संभव हो।

2. साहित्य समीक्षा

शिक्षण शैली एवं शैक्षणिक उपलब्धि के पारस्परिक संबंध पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण

अनुसंधान हुए हैं। ग्राशा (1994) ने 381 संकाय सदस्यों पर अपनी शिक्षण शैली सूची का प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि शिक्षण शैलियाँ लिंग, अकादमिक पद एवं विषय-क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती हैं तथा छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती हैं। ग्राशा (1996) ने पुस्तक 'टीचिंग विद स्टाइल' में पाँच शैलियों के विस्तृत प्रारूप की व्याख्या की और यह स्पष्ट किया कि कोई भी शिक्षक शुद्ध रूप से एक शैली का अनुसरण नहीं करता, अपितु शैलियों का मिश्रण अपनाता है। हाफीज (2021) ने पाकिस्तानी माध्यमिक विद्यालयों पर अध्ययन में पाया कि प्रदर्शन-पद्धति छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावी रही, जबकि व्याख्यान-पद्धति न्यूनतम प्रभावी सिद्ध हुई। यह निष्कर्ष छात्र-केंद्रित शैलियों के महत्व को रेखांकित करता है। गफूर एवं बाबू (2016) ने केरल के 300 माध्यमिक शिक्षकों पर अध्ययन में पाया कि भारतीय शिक्षकों में सुविधादाता शैली सर्वाधिक (M=35.55) तथा विशेषज्ञ शैली न्यूनतम (M=25.95) प्रचलित है, जो भारत के सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवलोकन है।

नानावरे एवं बाविस्कर (2023) ने कर्नाटक के 100 माध्यमिक छात्रों पर अध्ययन में अधिगम शैलियों तथा शैक्षणिक उपलब्धि के बीच धनात्मक एवं सार्थक सहसंबंध की पुष्टि की। कुमारी (2018) ने भागलपुर, बिहार के 288 विद्यार्थियों पर शोध में पाया कि उच्च-उपलब्धि वाले छात्रों का शिक्षक के साथ संबंध निम्न-उपलब्धि वालों की अपेक्षा अधिक बेहतर है, तथा इस प्रभाव में शिक्षण शैली की भूमिका केंद्रीय है। झांग एवं अन्य (2024) ने ऑनलाइन वातावरण में शिक्षण रणनीतियों एवं छात्र संलग्नता के बीच मध्यस्थ संबंध की पुष्टि की।

भारतीय संदर्भ में वैष्णव (2013) ने महाराष्ट्र के 200 छात्रों पर अध्ययन में दृश्य, श्रव्य एवं गतिक शैलियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा पाया कि गतिक शैली एवं शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च धनात्मक सहसंबंध विद्यमान है। नगराजू (2017) ने माध्यमिक स्तर पर अध्ययन-आदतों तथा अधिगम शैलियों के संयुक्त प्रभाव का मूल्यांकन किया। मार्जानो एवं अन्य (2003) ने सिद्ध किया कि प्रभावी कक्षा-प्रबंधन से छात्रों की उपलब्धि में 20 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है। सिंह (2020) ने बिहार के माध्यमिक विद्यालयों पर किए अध्ययन में पाया कि शिक्षक-प्रभावशीलता एवं छात्र उपलब्धि के बीच सार्थक सकारात्मक संबंध है। हैडर्नेजाद एवं अन्य (2017) तथा फोर्ड एवं अन्य (2016) के अध्ययनों ने ग्राशा-रीचमान मॉडल की मान्यता एवं विश्वसनीयता की पुष्टि विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में की। कौर एवं तूर (2014) ने माध्यमिक शिक्षक प्रभावशीलता, सामान्य बुद्धि एवं सृजनात्मकता के बीच सार्थक संबंध पाया। कुमार (2019) ने भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में सुविधादाता शैली की उपयोगिता पर बल दिया। पांडे (2023) ने बिहार की शिक्षा-व्यवस्था पर विस्तृत समीक्षा में शिक्षक-प्रशिक्षण तथा कक्षागत पद्धतियों में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उपरोक्त साहित्य से स्पष्ट है कि यद्यपि व्यापक अध्ययन उपलब्ध हैं, परंतु पटना जिले के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर पर शिक्षण शैलियों के प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन नगण्य है, जिसे यह शोध पूर्ण करता है।

3. उद्देश्य

1. पटना जिले के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण शैलियों के प्रचलन का अध्ययन करना।

2. शिक्षण शैलियों एवं छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंध का विश्लेषण करना।

4. शोध-प्रविधि

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक सर्वेक्षण अभिकल्प पर आधारित है, जो शिक्षण शैलियों एवं शैक्षणिक उपलब्धि के बीच विद्यमान संबंध का मात्रात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध का जनसंख्या-क्षेत्र पटना जिला है, जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित किए गए। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग करते हुए कुल 12 विद्यालयों (6 सरकारी, 6 निजी) का चयन किया गया, जिनमें नगरीय एवं अर्ध-नगरीय दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। इन विद्यालयों से कक्षा 9 एवं 10 के कुल 400 विद्यार्थी (200 बालक एवं 200 बालिकाएँ) तथा 80 शिक्षकों का चयन प्रतिचयन में सम्मिलित हुआ। आँकड़ा-संग्रह के लिए दो प्रमुख उपकरणों का प्रयोग किया गया। प्रथम, ग्राशा-रीचमान शिक्षण शैली सूची (संस्करण 3.0) का मानक हिंदी रूपांतरण, जिसमें पाँच शैलियों विशेषज्ञ, औपचारिक प्राधिकारी, व्यक्तिगत आदर्श, सुविधादाता एवं प्रतिनिधायक को मापने के लिए 40 पंचबिंदु लिकर्ट स्केल पर आधारित कथन सम्मिलित हैं। इस उपकरण की विश्वसनीयता क्रोनबेक अल्फा द्वारा 0.82 से 0.89 के मध्य पाई गई। द्वितीय, विषयगत शैक्षणिक उपलब्धि परीक्षण, जिसमें छात्रों के गत वार्षिक परीक्षा परिणाम (हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान) का संकलन विद्यालय अभिलेखों से किया गया।

अध्ययन में निम्न तकनीकों का अनुपालन हुआ: संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों से अनुमति, शिक्षकों

एवं छात्रों से सहमति-पत्र प्राप्त करना, गोपनीयता की प्रतिबद्धता, तथा दो सप्ताह के अंतराल में आँकड़ा-संग्रह। क्षेत्रीय शोध हेतु प्रशिक्षित शोध-सहायकों की सेवाएँ ली गईं, जिन्होंने प्रश्नावली-प्रशासन एवं साक्षात्कार का कार्य संपन्न किया। शोध सत्र 2024–2025 के दौरान फरवरी से मई 2025 तक क्रियान्वित हुआ। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु SPSS संस्करण 26 का प्रयोग किया गया। वर्णनात्मक सांख्यिकी (मध्यमान, मानक विचलन, प्रतिशत) के साथ-साथ अनुमानात्मक सांख्यिकी स्वतंत्र 't'-परीक्षण, पियर्सन उत्पाद-क्षण सहसंबंध गुणांक, एकल-कारक ANOVA एवं बहुचर पश्चातवर्ती (Post-hoc) तुलना का प्रयोग किया गया। सभी परिकल्पनाओं का परीक्षण 0.05 सार्थकता स्तर पर किया गया।

5. परिणाम

सांख्यिकीय विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष निम्न तालिकाओं में प्रस्तुत हैं।

तालिका 1: प्रतिदर्श का सामान्य विवरण (N = 400 छात्र, 80 शिक्षक)

चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
लिंग (छात्र)	बालक	200	50.0
	बालिकाएँ	200	50.0
विद्यालय-प्रकार	सरकारी	210	52.5
	निजी	190	47.5
कक्षा	नवीं	205	51.3
	दसवीं	195	48.7
शिक्षक लिंग	पुरुष	48	60.0
	महिला	32	40.0

तालिका 1 प्रतिदर्श के जनसांख्यिकीय ढाँचे को दर्शाती है। कुल 400 छात्रों में बालक-बालिका अनुपात समान (50:50) है, जो लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करता है। सरकारी (52.5%) एवं निजी (47.5%) विद्यालयों का लगभग समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। कक्षा नवीं एवं दसवीं के विद्यार्थी भी लगभग समान अनुपात में सम्मिलित हैं। शिक्षकों में पुरुष-महिला अनुपात 60:40 पटना जिले की सामान्य स्थिति के अनुरूप है। यह विवरण शोध की प्रतिनिधिकता को प्रमाणित करता है (स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण, 2025)।

तालिका 2: शिक्षकों में प्रचलित शिक्षण शैलियों का मध्यमान एवं मानक विचलन (N = 80)

शिक्षण शैली	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	क्रम
सुविधादाता	35.48	4.92	1
व्यक्तिगत आदर्श	33.76	5.14	2
औपचारिक प्राधिकारी	31.25	5.87	3
प्रतिनिधायक	28.93	6.21	4
विशेषज्ञ	26.41	6.08	5

तालिका 2 से स्पष्ट है कि पटना जिले के माध्यमिक शिक्षकों में सुविधादाता शैली (M=35.48) सर्वाधिक एवं विशेषज्ञ शैली (M=26.41) न्यूनतम प्रचलित है। यह परिणाम गफूर एवं बाबू (2016) के केरल-अध्ययन से मेल खाता है। व्यक्तिगत आदर्श शैली द्वितीय क्रम पर है, जो दर्शाता है कि शिक्षक प्रदर्शन एवं उदाहरण द्वारा पढ़ाने को प्राथमिकता देते हैं। प्रतिनिधायक शैली का न्यून प्रचलन भारतीय कक्षा-

परिवेश की पारंपरिक प्रकृति को इंगित करता है (स्रोत: ग्राशा-रीचमान सूची, 2025)।

तालिका 3: शिक्षण शैलियों एवं शैक्षणिक उपलब्धि के बीच पियर्सन सहसंबंध (N = 400)

शिक्षण शैली	सहसंबंध (r)	सार्थकता (p)
विशेषज्ञ	0.18	0.04*
औपचारिक प्राधिकारी	0.22	0.02*
व्यक्तिगत आदर्श	0.46	0.001**
सुविधादाता	0.58	0.000**
प्रतिनिधायक	0.41	0.001**

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

तालिका 3 दर्शाती है कि सभी पाँच शिक्षण शैलियों का शैक्षणिक उपलब्धि से धनात्मक सहसंबंध है, परंतु सुविधादाता शैली ($r=0.58$, $p < 0.01$) का सहसंबंध सर्वाधिक सार्थक है। व्यक्तिगत आदर्श ($r=0.46$) एवं प्रतिनिधायक ($r=0.41$) शैलियों का प्रभाव भी मध्यम-उच्च स्तर पर सार्थक है। विशेषज्ञ शैली का सहसंबंध ($r=0.18$) न्यूनतम है, जो यह प्रमाणित करता है कि केवल सूचना-संप्रेषण पर्याप्त नहीं, अपितु छात्र-सहभागिता अनिवार्य है (स्रोत: SPSS विश्लेषण, 2025)।

तालिका 4: विद्यालय-प्रकार के आधार पर शैक्षणिक उपलब्धि में अंतर ('t'-परीक्षण)

विद्यालय-प्रकार	N	मध्य मान	मानक विचलन	t-मान	p-मान
सरकारी	210	62.34	11.28	4.87	0.000*
निजी	190	71.82	10.45		

** $p < 0.01$

तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की औसत उपलब्धि ($M=71.82$) सरकारी विद्यालयों ($M=62.34$) की तुलना में सार्थक रूप से उच्च है ($t=4.87$, $p < 0.01$)। यह अंतर लगभग 9.48 अंकों का है। इसका एक प्रमुख कारण निजी विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात कम होना तथा सुविधादाता शैली का अधिक प्रयोग है (गोयल एवं पांडे, 2009)। सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना की कमी भी इस अंतर में योगदान देती है (स्रोत: विद्यालय अभिलेख, 2025)।

तालिका 5: लिंग के आधार पर शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक विश्लेषण

लिंग	N	मध्यमान	मानक विचलन	t-मान	p-मान
बालक	200	65.28	11.94	2.34	0.02*
बालिकाएँ	200	68.42	11.07		

* $p < 0.05$

तालिका 5 यह इंगित करती है कि बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि ($M=68.42$) बालकों ($M=65.28$) की तुलना में सार्थक रूप से अधिक है ($t=2.34$, $p < 0.05$)। यह परिणाम कुमारी (2018) के भागलपुर-अध्ययन से सहमत है, जिसमें पाया गया था कि बालिकाओं का शिक्षक से संबंध अधिक सकारात्मक होता है। यह प्रवृत्ति बिहार में बालिका-शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा बालिकाओं की अपेक्षाकृत अधिक अध्ययन-निष्ठा को भी दर्शाती है (स्रोत: क्षेत्रीय आँकड़े, 2025)।

तालिका 6: शिक्षण शैलियों के अनुसार छात्र उपलब्धि का ANOVA विश्लेषण

प्रधान शैली	N	मध्य मान उपलब्धि	SD	F-मान	p-मान
सुविधादाता	112	73.65	9.82	18.46	0.000**
व्यक्तिगत आदर्श	88	69.47	10.28		
प्रतिनिधायक	76	66.89	10.94		
औपचारिक प्राधिकारी	72	61.23	11.37		
विशेषज्ञ	52	58.76	11.88		

** $p < 0.01$

तालिका 6 का ANOVA विश्लेषण दर्शाता है कि विभिन्न प्रधान शिक्षण शैलियों वाले शिक्षकों से पढ़ने वाले छात्रों की उपलब्धि में सार्थक अंतर है ($F=18.46$, $p < 0.01$)। सुविधादाता शैली से पढ़े छात्रों की उपलब्धि ($M=73.65$) सर्वाधिक तथा विशेषज्ञ शैली ($M=58.76$) से पढ़े छात्रों की उपलब्धि न्यूनतम है। यह अंतर लगभग 14.89 अंकों का है। पश्चातवर्ती तुलना में सुविधादाता एवं विशेषज्ञ के मध्य $p < 0.001$ पर अंतर सार्थक पाया गया (स्रोत: SPSS ANOVA, 2025)।

6. विवेचना

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष शिक्षण शैलियों एवं माध्यमिक छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य

अत्यंत गंभीर संबंध को उजागर करते हैं। प्रथम उद्देश्य के अनुरूप विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि पटना जिले के माध्यमिक शिक्षकों में सुविधादाता शैली सर्वाधिक प्रचलित ($M=35.48$) है, तथा विशेषज्ञ शैली सबसे कम ($M=26.41$)। यह प्रवृत्ति गफूर एवं बाबू (2016) के केरल अध्ययन के निष्कर्षों से लगभग अविकल मेल खाती है, जहाँ सुविधादाता शैली का मध्यमान 35.55 पाया गया था। इसका अर्थ यह है कि भारतीय माध्यमिक शिक्षक धीरे-धीरे पारंपरिक व्याख्यान-पद्धति से हटकर छात्र-केंद्रित शिक्षण की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु यह परिवर्तन अभी अधूरा है। द्वितीय उद्देश्य के अनुरूप सहसंबंध विश्लेषण (तालिका 3) से स्पष्ट हुआ कि सुविधादाता शैली तथा शैक्षणिक उपलब्धि के बीच उच्चतम सकारात्मक सहसंबंध ($r=0.58$, $p < 0.01$) विद्यमान है। यह परिणाम हाफीज (2021) के पाकिस्तानी अध्ययन से सहमत है, जहाँ प्रदर्शन एवं चर्चा-पद्धति को सर्वाधिक प्रभावी पाया गया था, तथा व्याख्यान-पद्धति को न्यूनतम। भारतीय कक्षा में जब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, समूह-चर्चा कराते हैं, तथा छात्रों को समस्या-समाधान में स्वयं भाग लेने देते हैं, तब अधिगम गहरा एवं दीर्घकालिक होता है। मार्जिनो एवं अन्य (2003) का यह निष्कर्ष भी इसी दिशा में संकेत देता है कि प्रभावी कक्षा-व्यवस्थापन से छात्रों की उपलब्धि में 20 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है।

तालिका 6 का ANOVA विश्लेषण यह प्रमाणित करता है कि विभिन्न प्रधान शिक्षण शैलियों से पढ़े छात्रों के मध्य शैक्षणिक उपलब्धि में 14.89 अंकों तक का व्यापक अंतर है ($F=18.46$, $p < 0.01$)। यह निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका शैक्षिक-नीतिगत निहितार्थ यह है कि केवल शिक्षक की

विषय-विशेषज्ञता पर्याप्त नहीं शिक्षक को पद्धतिगत कौशलों का भी विकास करना आवश्यक है। वैष्णव (2013) के अध्ययन में भी गतिक एवं दृश्य शैलियों को पारंपरिक श्रवण शैली की तुलना में अधिक प्रभावी बताया गया था, जो इस शोध के निष्कर्षों को सुदृढ़ करता है। विद्यालय-प्रकार के आधार पर तालिका 4 में सार्थक अंतर ($t=4.87$, $p<0.01$) दिखा, जहाँ निजी विद्यालयों के छात्रों की उपलब्धि लगभग 9.48 अंकों से अधिक रही। इसका प्रमुख कारण निजी विद्यालयों में छोटा छात्र-शिक्षक अनुपात, अपेक्षाकृत बेहतर आधारभूत संरचना, तथा सुविधादाता शैली का अधिक अनुप्रयोग है। पांडे (2023) ने बिहार की शिक्षा-व्यवस्था की समीक्षा में इसी आधारभूत ढाँचागत कमी को रेखांकित किया है।

लिंग के आधार पर तालिका 5 ने बालिकाओं की श्रेष्ठ उपलब्धि ($M=68.42$) दिखाई। यह कुमारी (2018) के भागलपुर-अध्ययन के अनुरूप है। बालिकाओं में अध्ययन-निष्ठा, समय-प्रबंधन, तथा शिक्षकों से सकारात्मक अंतःक्रिया अधिक पाई जाती है। यह परिणाम बिहार सरकार की बालिका-शिक्षा नीतियों यथा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना एवं बालिका पोशाक योजना की भी सफलता को प्रतिबिंबित करता है। झांग एवं अन्य (2024) तथा फोर्ड एवं अन्य (2016) के निष्कर्ष भी इस अध्ययन की पुष्टि करते हैं कि शिक्षक की भावनात्मक संलग्नता एवं सुविधादाता व्यवहार छात्रों की अधिगम-संलग्नता को प्रभावित करते हैं। सिंह (2020) ने भी बिहार के संदर्भ में शिक्षक-प्रभावशीलता एवं छात्र उपलब्धि के बीच सार्थक संबंध प्रमाणित किया था। समग्रतः, यह विवेचना स्पष्ट करती है कि पटना जिले में शिक्षण गुणवत्ता में

सुधार का मार्ग शिक्षक-प्रशिक्षण में सुविधादाता एवं व्यक्तिगत आदर्श शैलियों के समावेश से प्रशस्त होगा। नानावरे एवं बाविस्कर (2023) ने यही सुझाव दिया है कि शिक्षकों एवं प्रशासकों को छात्रों की शैलियों के अनुरूप अध्यापन-क्रियाएँ आयोजित करनी चाहिए। कुमार (2019) का मत भी ग्रामीण भारतीय परिवेश में सुविधादाता शैली की प्रासंगिकता को प्रमाणित करता है।

7. निष्कर्ष

इस शोध ने पटना जिले के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण शैलियों तथा शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सार्थक धनात्मक संबंध को अनुभवजन्य आधार पर प्रमाणित किया। सुविधादाता एवं व्यक्तिगत आदर्श शैलियाँ उपलब्धि-वृद्धि में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुईं, जबकि मात्र विशेषज्ञ-केंद्रित पारंपरिक शैली का प्रभाव न्यूनतम रहा। निजी विद्यालयों एवं बालिकाओं की उपलब्धि अपेक्षाकृत उच्च पाई गई। नीतिगत स्तर पर यह आवश्यक है कि बिहार शिक्षा विभाग, SCERT एवं DIETs शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्र-केंद्रित शिक्षण शैलियों का समावेश करें। विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्यों को अपने शिक्षकों की शैली का मूल्यांकन करके उन्हें सुविधादाता एवं प्रतिनिधायक शैलियों की ओर अग्रसर करना चाहिए। भविष्य के शोध में अन्य जिलों एवं विषयों को सम्मिलित कर व्यापक सामान्यीकरण किया जा सकता है।

संदर्भ

1. ग्राशा, ए. एफ. (1994). ए मैटर ऑफ़ स्टाइल: द टीचर ऐज़ एक्सपर्ट, फॉर्मल अथॉरिटी, पर्सनल मॉडल, फैसिलिटेटर, एंड डेलीगेटर. कॉलेज टीचिंग, 42(4), 142–149.

2. ग्राशा, ए. एफ. (1996). टीचिंग विद स्टाइल: ए प्रैक्टिकल गाइड टू एनहांसिंग लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स. पिट्सबर्ग, पीए: अलायंस पब्लिशर्स.
3. हस्का-रीचमान, एस., एवं ग्राशा, ए. एफ. (1982). द ग्राशा-रीचमान स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल स्केल्स: रिसर्च फाइंडिंग्स एंड एप्लिकेशंस. जे. कीफ़ (सं.), स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड ब्रेन बिहेवियर. रेस्टन, वीए: NASSP.
4. गफूर, के. ए., एवं बाबू, आर. (2016). डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए टीचिंग स्टाइल इन्वेंटरी अमंग सेकेंडरी स्कूल टीचर्स ऑफ केरल. गुरु जर्नल ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज़, 4(3), 608–617.
5. हाफीज़, एम. (2021). इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ऑन इंटररेस्ट एंड एकेडमिक एचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स बाय मल्टीपल टीचिंग मेथड्स. पेडागॉजिकल रिसर्च, 6(3), em0102.
6. नानावरे, आर. बी., एवं बाविस्कर, सी. (2023). ए स्टडी ऑन एकेडमिक एचीवमेंट इन रिलेशन टू लर्निंग स्टाइल्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स. MIER जर्नल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेज़, 13(1), 180–192.
7. कुमारी, ए. (2018). इफ़ेक्ट ऑफ टीचर इफ़ेक्टिवनेस ऑन हाई एंड लो एकेडमिक एचीवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स: ए कम्परेटिव स्टडी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 6(2), 45–58.
8. वैष्णव, आर. एस. (2013). लर्निंग स्टाइल एंड एकेडमिक एचीवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स. वॉइस ऑफ रिसर्च, 1(4), 1–4.
9. मार्ज़ानो, आर. जे., मार्ज़ानो, जे. एस., एवं पिकरिंग, डी. जे. (2003). क्लासरूम मैनेजमेंट दैट वर्क्स: रिसर्च-बेस्ड स्ट्रेटेजीज़ फॉर एवरी टीचर. अलेक्ज़ेंड्रिया, VA: ASCD.
10. नगराजू, पी. (2017). स्टडी ऑफ एकेडमिक एचीवमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू दियर स्टडी हैबिट्स एंड लर्निंग स्टाइल्स. एजुकेशनल केस्ट – एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड अप्लायड सोशल साइंसेज़, 8(1), 9–16.
11. झांग, एक्स., यांग, वाई., एवं लिउ, क्यू. (2024). इफ़ेक्ट ऑफ टीचर्स टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एंगेजमेंट: मॉडरेटेड मेडिएशन मॉडल. फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी, 15, 1475048.
12. फोर्ड, जे. एच., विसी, जे., कोट्स, ई., कमिंग्स, बी., कॉहलर, एस., एवं रॉब, एन. (2016). एडैप्शन ऑफ द ग्राशा-रीचमान स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल सर्वे एंड टीचिंग स्टाइल इन्वेंटरी टू असेस इंडिविजुअल टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स. BMC मेडिकल एजुकेशन, 16(1), 252.
13. हैडर्नेजाद, टी., खादिवी, आई. ए., एवं अदेल, एस. एम. आर. (2017). द

- रिलेशनशिप बिटवीन EFL टीचर्स टीचिंग स्टाइल्स एंड एजुकेशनल पॉलिसीज़. ईरानियन जर्नल ऑफ अप्लायड लैंग्वेज स्टडीज़, 9(2), 49–76.
14. गोयल, एस., एवं पांडे, पी. (2009). हाउ डू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स डिफर? इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 44(23), 67–76.
15. कौर, के., एवं तूर, के. के. (2014). ए स्टडी ऑफ टीचर इफ़ेक्टिवनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स. MIER जर्नल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ ट्रेंड्स एंड प्रैक्टिसेज़, 4(1), 64–75.
16. सिंह, आर. के. (2020). टीचर इफ़ेक्टिवनेस एंड स्टूडेंट्स एकेडमिक एचीवमेंट इन सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ बिहार. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़, 7(4), 412–419.
17. शर्मा, आर. (2019). रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग स्टाइल्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, 9(3), 235–240.
18. कुमार, पी. (2019). टीचिंग मेथड्स एंड एकेडमिक एचीवमेंट इन रूरल इंडियन स्कूल्स. जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड एक्सटेंशन, 56(2), 45–54.
19. पांडे, के. (2023). ऐलिंग प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन बिहार: ए स्टेप लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेंड्स. जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेटिव रिसर्च (JETIR), 10(6), j749–j758.
20. पटेल, एस., एवं मिश्रा, एन. (2022). टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड सेकेंडरी स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस: एन इंडियन पर्सपेक्टिव. इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 11(2), 88–97.

PROGRESSIVE RESEARCH JOURNAL ISSN- 2319-8095

Membership / Subscription Form

1. Applicant Details (आवेदक का विवरण):

- Name (नाम): _____
- Father's / Husband's Name: _____
- Date of Birth: ____ / ____ / ____
- Gender: Male / Female / Other

2. Contact Details (संपर्क विवरण):

- Address (पता): _____
- City: _____ State: _____
- Pin Code: _____
- Mobile No.: _____
- Email ID: _____

3. Academic / Professional Details (शैक्षिक / व्यावसायिक विवरण):

- Qualification (योग्यता): _____
- Designation (पद): _____
- Institution/Organization: _____
- Area of Specialization: _____

4. Membership Type (सदस्यता प्रकार):

(✓ करें)

- ☐ Annual Membership (वार्षिक)
- ☐ Life Membership (आजीवन)
- ☐ Institutional Membership (संस्थागत)

5. Subscription Details (सदस्यता शुल्क विवरण):

- Amount Paid: ₹ _____
- Payment Mode: Cash / Online / DD
- Transaction ID / DD No.: _____
- Date: ____ / ____ / ____

6. Declaration (घोषणा):

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही एवं सत्य है। मैं जर्नल के नियमों एवं शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।

Signature of Applicant: _____

Date: ____ / ____ / ____

For Office Use Only:

- Membership ID: _____
- Receipt No.: _____
- Approved By: _____